दिसंबर 2021
खंड - XXXVII | अंक - IV

एक्ज़िमिअस: निर्यात लाभ

इस अंक में

- विश्व आर्थिक परिदृश्य: अक्टूबर अपडेट
- डंपिंग-रोधी शुल्क: भारत और भावी राह
- निर्यात संवर्धन के लिए बुनियादी ढांचागत सुविधाओं को बढ़ाना
- कारोबारी आंकड़ों की गलत रिपोर्टिंग और अनौपचारिक पूंजी प्रवाह –
- आकलन, कारण और समाधान
- सेमीकंडक्टर की वैश्विक कमी
- अंतरिक्ष उद्योग
- एक्ज़िम बाज़ार

त्रैमासिक प्रकाशन:

इंडिया एक्ज़िम बैंक

केन्द्र एक भवन, 21वीं मंज़िल,
विश्व व्यापार केन्द्र संकुल, कफ़ परेड,
मुंबई – 400 005.
फोन: 022 2217 2600
ईमेलः ccg@eximbankindia.in
www.eximbankindia.in
www.eximmitra.in

विश्व आर्थिक परिदृश्य: अक्टूबर अपडेट

कोरोना वायरस महामारी से गंभीर रूप से प्रभावित होने के बाद विश्व अर्थव्यवस्था के उबरने का क्रम जारी रहा। हालांकि कोविड के नए और ज्यादा संक्रामक स्वरूपों के कारण सुधार की यह रफ्तार कुछ कमजोर पड़ी। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े महत्त्वपूर्ण स्थानों पर कोविड महामारी का संक्रमण फैलने के कारण आपूर्ति उम्मीद से कहीं अधिक बाधित रही। जिससे कई देशों में महंगाई और बढ़ गई। कुल मिलाकर, आर्थिक संभावनाओं के लिए जोखिम बढ़ गया और नीतिगत दुविधाएं अधिक जटिल हो गईं।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के अक्टूबर-2021 के लिए विश्व आर्थिक पूर्वानुमान की समीक्षा में वैश्विक जीडीपी विकास दर के अनुमान को जुलाई-2021 के 6% से कम कर अक्टूबर में 5.9% कर दिया गया। साल 2021 के लिए यह कमी अंशतः उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में आपूर्ति बाधित होने के कारण आई गिरावट और मुख्य रूप से कम आय वाले विकासशील देशों में महामारी के कारण बदतर हुए हालात के परिणाम स्वरूप रही। कमोडिटी निर्यातक उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में से निकट भविष्य में कुछ में मजबूत संभावनाएं सामने आने से इस गिरावट को आंशिक तौर पर संतुलित किया गया। पूर्वानुमान में 2022 में लगभग 5% वृद्धि, उसके बाद 2023 और 2026 तक 3% से अधिक वार्षिक वृद्धि अनुमानित है। हालांकि महंगाई का दबाव और महामारी के हालात से जुड़ी अनिश्चितताओं को वैश्विक विकास के लिए प्रमुख खतरा भी माना जा रहा है।

अब विकास की विशिष्टताओं में टीकाकरण अभियान का संचालन, नीतिगत सहयोग और निरंतर वित्तीय सहायता प्रदान करने जैसे पहलू शामिल होंगे। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के लिए वृद्धि की संभावनाओं को जुलाई के पूर्वानुमान की तुलना में 0.4% कम आंका गया, जो आपूर्ति श्रृंखला की बाधाओं, प्रमुख सामग्री की कमी और व्यापक संक्रमण की स्थितियों को परिलक्षित करता है। उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए पूर्वानुमान विश्व आर्थिक मंच के जुलाई-2021 की अद्यतन जानकारी की तुलना में मामूली अधिक रहा, जो ज्यादातर क्षेत्रों में वृद्धि को प्रदर्शित करता है। कम आय वाले विकासशील देशों में वृद्धि का पूर्वानुमान जुलाई की तुलना में 0.6% कम रहा। इन देशों में टीकाकरण कार्यक्रम की धीमी रफ्तार अर्थव्यवस्था के उबरने में प्रमुख बाधा बनी। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि तमाम देशों की अर्थव्यवस्था में कुछ न कुछ विचलन की स्थिति अभी बनी हुई है। इस बीच, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में सकल उत्पादन 2022 में महामारी के पूर्व की स्थिति में और 2024 में उससे 0.9% अधिक रहने की उम्मीद है। वहीं, उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के समूह (चीन को छोड़कर) के लिए कुल उत्पादन 2024 में महामारी के पूर्व के अनुमान से 5.5% कम रहने की आशंका है। फलस्वरूप, उनके जीवन स्तर में सुधार के लिए यह एक बड़ा झटका है।

आर्थिक भिन्नता की यह स्थिति वैक्सीन तक पहुंच और नीतिगत सहायता में विशाल असमानता के कारण बनी है। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में एक तरफ, लगभग 60% आबादी का टीकाकरण हो गया है। कहीं-कहीं अब बूस्टर

डोज भी लगने लगी हैं। वहीं, कम आय वाले देशों में करीब 96% आबादी को अब भी टीके नहीं लगे हैं। कठिन वित्तीय परिस्थतियों और महंगाई दर की उम्मीदों के पटरी से उतरने के बड़े खतरे का सामना कर रही उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं उत्पादन में व्यापक कमी के बावजूद अधिक शीघ्रता से नीतिगत सहायता वापस ले रही हैं।

उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में तो एक तरफ व्यापक वित्तीय सहायता जारी है। वहीं, दूसरी तरफ कई उभरते आर्थिक बाजारों में नीतिगत सहायता की गुंजाइश सीमित हो गई है। महामारी के फैलने की स्थिति के बीच वहां नीतिगत सहायता लगातार घट रही है। माना जा रहा है कि उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के प्रमुख केंद्रीय बैंक 2022 के अंत तक नीतिगत दरों में परिवर्तन नहीं करेंगे। फिर भी, किन्हीं-किन्हीं देशों में जारी प्रक्रिया के दौरान ही परिसंपत्ति क्रय कम किए जाने की संभावना है। जैसे- ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में। इस बीच ब्राजील, चिली, मेक्सिको और रूस सहित कुछ उभरते बाजारों के केंद्रीय बैंक भी कम समायोजन वाला रुख अपनाने लग गए हैं।

आपूर्ति बाधाओं के कारण कई चुनौतियां उत्पन्न हुई हैं। एक ओर प्रमुख सामग्री की कमी के कारण विभिन्न देशों में विनिर्माण गतिविधियों में कमी आई है। वहीं दूसरी तरफ, आपूर्ति में कमी के बीच ही उपभोक्ता वस्तुओं की दबी हुई मांग फिर उभर आई। इससे उपभोक्ता उत्पादों की कीमतों में फिर उछाल आया और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में तेजी से वृद्धि हुई है। इसके बाद जहां तक वैश्विक व्यापार का सवाल है, तो अस्थायी रुकावटों के बावजूद इसमें 2021 में करीब 10% वृद्धि अनुमानित है। इसके बाद 2022 में करीब 7% की सामान्य वृद्धि अनुमानित है। तब तक विश्व-व्यापार में धीरे-धीरे सामान्य स्थिति बहाल होने का भी अनुमान है। वहीं, मध्यम अवधि में वैश्विक व्यापार वृद्धि लगभग 3.5% तक रह सकती है। समग्र व्यापार बहाली के चलते पर्यटन पर निर्भर अर्थव्यवस्थाओं और खास तौर पर सीमा पार सेवाओं के लिए मंद पड़ी संभावनाओं में भी सुधार के आसार हैं।

हाल के घटनाक्रम से साफ हो गया है कि वर्तमान परिस्थितियां हम सब को समान रूप से प्रभावित कर रही हैं। साथ में यह भी कि जब तक यह महामारी किसी भी एक जगह बनी हुई है, इसे पूरी तरह खत्म नहीं माना जा सकता है। आईएमएफ का पूर्वानुमान है कि यदि कोविड-19 ने मध्यम अवधि में दूरगामी प्रभाव डाला, तो इससे वैश्विक जीडीपी में मौजूदा अनुमान की तुलना में, अगले 5 वर्षों में समग्र रूप से 5.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर तक की गिरावट आ सकती है।

आईएमएफ के अनुसार, विश्व आबादी का टीकाकरण तेज करने के साथ ही व्यापक टेस्टिंग और उपचार पर निरंतर जोर, इस समय की सर्वोच्च नीतिगत प्राथमिकता है। यह लाखों जानें बचाने और वायरस के नए स्वरूपों को सामने आने से रोकेगा। इस बीच, यह सुनिश्चित करना महत्त्वपूर्ण है कि वित्तीय रूप से सीमित संसाधन वाले देश अन्य दायित्वों के निर्वाह के साथ आवश्यक खर्च जारी रख सकें। वैश्विक समुदाय को व्यावसायिक तनावों को सुलझा कर पिछले कुछ वर्षों में लागू किए गए व्यापारिक प्रतिबंधों को वापस लेना चाहिए। इस प्रकार से नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को मजबूत करना चाहिए। प्रयास इस बात के भी होने चाहिए कि किसी वैश्विक न्यूनतम कॉर्पोरेट कर के बाबत समझौता हो जाए। इससे अपने हित के लिए मानकों के साथ लगातार छेड़छाड़ की प्रतिस्पर्धा रुकेगी। साथ ही, महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक निवेश के लिए धन जुटाने के मकसद से वित्तीय संसाधन बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।

राष्ट्र के लिए इस समय ऐसी मिश्रित नीतियां बनाने की जरूरत है, जो महामारी के स्थानीय हालात और आर्थिक परिस्थितियों पर आधारित हों। उनका लक्ष्य अधिकतम सतत रोजगार को प्रोत्साहित करना होना चाहिए। बजट खर्च के मामले में, कहां-कितना सहयोग-समर्थन दिया जाना है, यह इस बात पर निर्भर करता कि महामारी किस चरण में है। इस समय स्वास्थ्य-सुविधाओं संबंधी व्यय किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए प्राथमिकता पर है। कुछ देशों में सीमित राजकोषीय स्थितियों को देखते हुए बजट खर्च एकदम लक्ष्य-केंद्रित होना चाहिए। मतलब, जो सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र हों वहां वित्तीय सहायता अधिक दी जानी चाहिए। साथ ही, पुनर्आवंटन संबंधी पहलों और पुनर्प्रशिक्षण के लिए भी वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए। इसके बाद, अर्थव्यवस्था की सतत बहाली और लंबी अवधि के संरचनात्मक लक्ष्यों में निवेश जैसे उपायों पर बल दिया जाना चाहिए। ऋण निरंतरता को सुनिश्चित की जानी चाहिए और विवेकसम्मत राजस्व एवं व्यय उपायों वाला एक मध्यम अवधि का फ्रेमवर्क बनाया जाना चाहिए।

जहां तक मौद्रिक नीति का सवाल है, तो केंद्रीय बैंक आम तौर पर अस्थायी महंगाई दबावों को अधिक ध्यान में रखते हैं। ऐसे में कीमतों के स्तर पर अगर बड़ा उतार-चढ़ाव नहीं होता तो उन्हें मौद्रिक नीति में सख्ती बरतने से परहेज करना चाहिए। आईएमएफ का सुझाव है कि अर्थव्यवस्था की बहाली अगर उम्मीद से तेज हो और महंगाई दर बढ़ने का जोखिम भी यदि तय हो, तो प्राधिकारियों को शीघ्रता से कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन ऐसी स्थिति में, जहां न्यून रोजगार दर के बीच महंगाई दर बढ़ रही हो और इनके असंतुलित होने का जोखिम पुख्ता हो, तो मौद्रिक नीति को सख्त बनाने की जरूरत होती है, ताकि मूल्य दबाव न बनने पाए। फिर भले ही इससे रोजगार-बहाली में विलंब ही क्यों न होता हो। इसके विपरीत, जहां महंगाई दर का दबाव सीमित है, उसका अनुमान केंद्रीय बैंक के लक्ष्य से कम है और श्रम बाजार की मंदी बनी हुई है, वहां मौद्रिक नीति समायोजनपूर्ण बनी रह सकती है।

अंत में महामारी के बाद की अर्थव्यवस्था की चुनौतियों पर आईएमएफ खास जोर देता है। जैसे कि संचित मानव पूंजी को महामारी ने झटका दिया है, उसे बेअसर करना। हरित प्रौद्योगिकी और डिजिटलीकरण से संबंधित विकास अवसरों के लिए सुविधाएं प्रदान करना। असमानता को कम करना और दीर्घावधि विकास के लिए सार्वजनिक वित्त की निरंतरता सुनिश्चित करना। ■

डंपिंग–रोधी शुल्क : भारत और भावी राह

विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) 'डंपिंग' को एक ऐसी कार्रवाई के रूप में परिभाषित करता है, जिसमें कोई कंपनी किसी उत्पाद को अपने ही घरेलू बाजार में उसकी 'सामान्य कीमत' से कम पर निर्यात करती है। डब्ल्यूटीओ का डंपिंग–रोधी करार विभिन्न देशों को इस तरह कार्रवाई करने की अनुमति देता है, जिससे वे व्यापार एवं शुल्क संबंधी सामान्य समझौते 'गैट' (जीएटीटी) के बाध्यकारी प्रावधानों से अपने लिए कुछ छूट ले सकें। 'गैट' के प्रावधानों के तहत विभिन्न देशों के लिए कुछ बाध्यकारी शुल्क और व्यापारिक भागीदारों के बीच भेदभाव न करने की व्यवस्था की गई है। डंपिंग–रोधी करार ये दिशानिर्देश तय करता है कि सरकारें, (फर्म नहीं) डंपिंग–रोधी कार्रवाईयों को अनुशासित करते हुए डंपिंग पर प्रतिक्रिया कर सकती हैं या नहीं। खास तौर पर अगर प्रतिस्पर्धी घरेलू उद्योग को कहीं वास्तविक (या भौतिक) नुकसान हुआ है, तो यह करार वहां सरकारों को डंपिंग के विरुद्ध कार्रवाई की छूट देता है।

डब्ल्यूटीओ के अनुसार वैश्विक रूप से पिछले 5 वर्षों में सर्वाधिक डंपिंग–रोधी कार्रवाई आधार धातुओं और वस्तुओं के लिए की गई है। इसके बाद रसायन, प्लास्टिक और वस्त्रों का नंबर आता है। ऐसे क्षेत्र, जहां डंपिंग–रोधी कार्रवाइयां बिल्कुल भी नहीं की गईं, उनमें पशु और वनस्पति तेल; खाल, चमड़ा और उससे बनीं वस्तुएं; जूते–चप्पल; और कीमती रत्न तथा धातुएं शामिल हैं। यह संकेत करता है कि डंपिंग से जुड़ी व्यापारिक राहत के अधिकांश कदम उन उत्पादों के लिए लागू किए गए, जो औद्योगिक उपयोग के हैं।

यह गणना करने के कई तरीके हैं कि कोई विशिष्ट उत्पाद भारी मात्रा में या केवल मामूली रूप से डंप किया गया है या नहीं। किसी उत्पाद के 'सामान्य मूल्य' की गणना के लिए समझौते में तीन विधियां बताई गई हैं।

- गणना की पहली विधि निर्यातक के घरेलू बाजार में कीमत पर आधारित है।
- ऐसी स्थिति में जब पहली विधि काम नहीं आ रही हो, तो दो अन्य विकल्प इस तरह हैं। एक–निर्यातक द्वारा अन्य देश के लिए निर्धारित अपने उत्पाद की कीमत। दूसरा–निर्यातक की उत्पादन लागत, अन्य व्यय और सामान्य मुनाफा के मेल पर आधारित गणना।

करार में यह भी उल्लेख किया गया है कि निर्यात मूल्य और सामान्य कीमत क्या होती है। इसके बीच उचित तुलना कैसे की जा सकती है।

भारतीय परिदृश्य

भारत में डंपिंग–रोधी और अनुदान–रोधी तथा प्रतिकारी (काउंटरवेलिंग) उपायों संबंधी कार्य वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय देखता है। इस मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में कार्यरत पाटनरोधी और संबद्ध शुल्क महानिदेशालय (डीजीएडी) यह जिम्मेदारी उठाता है। पदनामित अधिकारी इसका प्रमुख होता है। पदनामित अधिकारी का काम डंपिंग–रोधी/अनुदान–रोधी और प्रतिकार शुल्क संबंधित जांच और डंपिंग–रोधी या अनुदान–रोधी उपायों के लिए सरकार से सिफारिश करना है। इस प्रकार का शुल्क अंतिम रूप से वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के द्वारा लगाया जाता है। इस तरह वाणिज्य मंत्रालय डंपिंग–रोधी शुल्क की अनुशंसा करता है। जबकि इस शुल्क को वसूल करने का कार्य वित्त मंत्रालय का है। जून–2021 की स्थिति में भारत दूसरे सर्वाधिक डंपिंग–रोधी उपाय (313) करने वाले देशों में था, जो अमेरिका के बाद सर्वाधिक हैं। इस पर गौर किया जा सकता है कि भारत ने 2021–22 में 400 बिलियन यूएस डॉलर के निर्यात का लक्ष्य रखा है। चुनिंदा क्षेत्रों में डंपिंग–रोधी शुल्क को खत्म करना या कम करना इस लक्ष्य को हासिल करने और भारत के लिए आने वाले वर्षों में भी निर्यात वृद्धि की दिशा में महत्त्वपूर्ण कारक होगा। यदि कच्चे माल के आयात पर डंपिंग–रोधी शुल्क खत्म किया जाता है, तो यह प्रतिस्पर्धी मूल्य पर उसके आयात को समर्थन देगा। इससे कच्चे माल की कीमतों में कमी होगी और छोटे उद्योगों को लाभ मिलेगा। कच्चे माल के आयात मूल्य में कमी का नतीजा यह होगा कि इस तरह के उद्योग कम कीमत पर अपने उत्पादों का निर्यात कर सकेंगे। इस प्रकार जीवीसी एकीकरण से लाभ के अधिक अवसर सुनिश्चित होंगे।

इस संबंध में बहुत ही जायज प्रकरण विस्कॉस स्टैपल फाइबर पर डंपिंग–रोधी शुल्क का हटाया जाना है:

- भारत विस्कॉस स्टैपल फाइबर के शीर्ष 10 आयातकों में से है (एचएस 550410)। इसके आयात में 2011–20 के दौरान 7.1% एएजीआर दर्ज की गई। जबकि इसी अवधि के दौरान विश्व आयात में 2.5% की ऋणात्मक एएजीआर दर्ज की गई।
- विस्कॉस स्टैपल फाइबर पर डंपिंग–रोधी शुल्क हटाने से भारत में वस्त्र उद्योग की छोटी इकाइयां अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी कीमतों पर फाइबर हासिल कर सकती हैं। वे विस्कॉस आधारित उत्पादों के निर्यात में वृद्धि कर सकती हैं।
- इसके अतिरिक्त, इससे भारत से मूल्यवर्धित वस्त्र उत्पादों के निर्यात में वृद्धि हो सकती है। इससे वैश्विक मूल्य श्रृंखला में उसकी स्थिति सुदृढ़ होगी।

डंपिंग–रोधी शुल्क के विकल्प

डंपिंग–रोधी शुल्क का मूल उद्देश्य, विदेशी इकाइयों द्वारा बहुत सस्ती कीमतों पर माल की आपूर्ति कर घरेलू निर्माताओं और निर्यातकों को पहुंचाए जा सकने वाले नुकसान से बचाना है। हालांकि इस प्रकार के शुल्कों को लागू करने के आधार में विसंगतियां भी हैं। उदाहरण के लिए, एक घरेलू फर्म जो अपनी कीमतें अधिक रखना चाहती है, वह विदेशी फर्मों के खिलाफ डंपिंग–रोधी याचिका लगा सकती है। ताकि विदेशी फर्मों पर यह दबाव बनाया जा सके कि वे घरेलू इकाइयों द्वारा तय कीमतों के हिसाब से अपने उत्पाद की कीमतें तय करें। इस तरह के मामलों में घरेलू उद्योग प्राथमिक रूप से विदेशी फर्मों को बाध्य कर रहे हैं कि वे उनके साथ मिलकर उत्पाद की कीमतें ऊंची रखें।

- मूल्यों में इस प्रकार की विसंगतियों पर निगरानी रखने और उन्हें खत्म करने के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के तहत एक शिकायत निवारण फोरम गठित किया जा सकता है। अन्यथा ये विसंगतियां घरेलू और विदेशी फर्मों के बीच टकराव या मिलीभगत की स्थिति पैदा कर सकती हैं।
- आपस में व्यापारिक समझौता करने वाले देश करार में एक उपबंध जोड़ सकते हैं। इसमें दोनों देश उत्पादों की डंपिंग रोकने की व्यवस्था कर सकते हैं। आपसी सहमति दे सकते हैं।
- इस तरह, डंपिंग–रोधी नियमों की तुलना में डंपिंग की मौजूदा दिक्कत को दूर करने के लिए सुरक्षा–उपाय करना ज्यादा प्रभावी हो सकता है। हालांकि मौजूदा नियमों में अभी ऐसा नहीं है कि घरेलू उद्योग को यह बताना पड़ेगा कि विदेशी फर्म गलत तरीके से अपने उत्पाद की कीमतें तय कर रही हैं। लेकिन घरेलू फर्मों को यह जरूर बताना होता है कि उनसे जुड़े उत्पाद का आयात बढ़ने से उनके हितों को गंभीर चोट पहुंची है। यह अपेक्षा सरकारी मदद हासिल करने के मापदंडों का स्तर ऊंचा करती है। साथ ही नुकसान पहुंचने के ओछे और अनैतिक आरोपों को भी हतोत्साहित करती है। ■

निर्यात संवर्धन के लिए बुनियादी ढांचागत सुविधाओं को बढ़ाना

व्यापार के लिए सुविधा प्रदान करने में बुनियादी ढांचे की अहम भूमिका होती है। ऐसे बहुत प्रमाण मिलते हैं कि बेहतर अवसंरचना वाले हांगकांग और सिंगापुर जैसे देश अंतरराष्ट्रीय कारोबार में न सिर्फ अच्छी प्रगति करते हैं, बल्कि अपनी क्षमता से बढ़कर प्रदर्शन करते हैं। जबकि कमजोर अवसंरचना वाले देश जैसे कि भूटान और पाकिस्तान में तुलनात्मक रूप से बाहरी क्षेत्र कम विकसित हैं। अवसंरचना का व्यापार में मुख्यतया इसलिए महत्त्व है क्योंकि इससे लागत में कमी आती है और कारोबार में सुगमता सुनिश्चित होती है। निम्न व्यापारिक लागतों से निर्यात की प्रतिस्पर्धी कीमतों में सुधार आता है, निर्यात की संभावनाएं बढ़ती हैं, क्षेत्रीय और अंतर-क्षेत्रीय व्यापार तेज होता है और व्यापारिक घाटा कम होता है।

भारत में दुनिया का दूसरा सबसे लंबा 5.9 मिलियन किलोमीटर सड़क नेटवर्क है, लेकिन कुल सड़क नेटवर्क में राष्ट्रीय राजमार्ग का हिस्सा 2.7% से भी कम है और इस पर 40% सड़क यातायात संचालित होता है। इसके अतिरिक्त, 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार, देश की आधे से ज्यादा सड़कें डामरीकृत नहीं हैं और करीब 77.9% राजमार्ग केवल दो या दो से कम लेन[1] वाले हैं। भारत में विश्व का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क भी है, जो 1.2 लाख किलोमीटर में फैला हुआ है। तथापि मालगाड़ियों की औसत गति भारत में 24-25 किमी प्रति घंटा है। यह तुलनात्मक रूप से अमेरिका और चीन[2] में 38-40 किमी प्रति घंटा है। मात्रा के मामले में भारत के 90% व्यापार वहन करने वाले बंदरगाहों के भी आधुनिकीकरण की सख्त जरूरत है। भारतीय बंदरगाहों में माल पहुंचने से लेकर पूरा होने की प्रक्रिया का औसत समय 2.59 दिन है जो 0.97 दिन[3] के विश्व औसत से बहुत अधिक है। अवसंरचना संबंधी खामियां और लॉजिस्टिक दक्षता में कमी भारतीय अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ बढ़ाती है और अंतरराष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करती है।

अवसंरचना विकास में राज्यों की भूमिका

अवसंरचना में कमियों को दूर करने की पहल में राज्यों की बहुत बड़ी हिस्सेदारी होती है। ऐसा राज्य, जहां पर्याप्त और उच्च गुणवत्ता की भौतिक अवसंरचना जैसे कि बिजली की अबाध आपूर्ति, मल्टीमॉडल परिवहन और लॉजिस्टिक अवसंरचना तथा दूरसंचार नेटवर्क इत्यादि हैं, वहां व्यापार और उत्पादन लागतें कम हो जाती हैं। इससे अधिक कारोबार आकर्षित होता है और राज्य में निर्यात संबंधित गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलता है। राज्य, व्यापार के अनुकूल अवसंरचना विकसित करने के क्रम में तमाम खामियों को दूर कर अपनी निर्यात स्पर्धात्मक क्षमता बढ़ा सकते हैं। राज्य की अपनी अनोखी विशिष्टता के अनुसार अवसंरचना की जरूरत भिन्न-भिन्न हो सकती है। उदाहरण के लिए, तटीय राज्यों को बंदरगाह के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के साथ-साथ उत्पादन स्थल से बंदरगाह तक कार्गो के परिचालन में सुविधा प्रदान करने के लिए सड़क और रेल नेटवर्क को सुदृढ़ करने की जरूरत है। वहीं, बंदरगाहविहीन राज्यों को आईसीडी/सीएफएस पर अधिक निवेश करने की आवश्यकता है।

परिवहन संपर्क

नीति आयोग का निर्यात तत्परता सूचकांक (ईपीआई) राज्यों/केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर निर्यात संवर्धन के आधारभूत क्षेत्रों को चिह्नित करता है। परिवहन अवसंरचना इसके मुख्य स्तंभों में से एक है, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और दिल्ली सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाले राज्यों/केंद्र शासित प्रदेश के रूप में सामने आए हैं। इन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में एक समान कारक है कि सभी में बहुत अच्छी हवाई कार्गो सुविधाएं, मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक केंद्र के साथ-साथ इनलैंड कंटेनर डिपो हैं। इससे माल का सुचारू परिवहन हो पाता है और इन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में निवेश आकर्षित करता है। पर्वतीय राज्यों का प्रदर्शन इस श्रेणी में खराब रहा है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को छोड़कर अन्य हिमालयी राज्यों (त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर) में माल परिवहन प्रबंधन मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक केंद्रों के साथ ही इनलैंड कंटेनर डिपो का अभाव है।

उल्लेखनीय है कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा परिकल्पित राष्ट्रीय एकल खिड़की इंटरफेस प्रणाली, अनुमोदन और मंजूरियों की प्रणाली में क्रान्तिकारी बदलाव ला सकती है। इसके पहले चरण में 17 मंत्रालयों/विभागों और 14 राज्यों की भागीदारी है। इसमें निर्यात के विविध आयामों को एकीकृत करना चाहिए जिससे कि आंतरिक और बाहरी, दोनों व्यापार तथा निवेश परिवेश को प्रोत्साहन मिले। राज्यों को आवश्यक निर्यात अवसंरचना के विकास और सुदृढ़ीकरण के लिए केंद्र सरकार की निर्यात व्यापार अवसंरचना योजना (टीआईईएस) में प्रदान की जाने वाली सहायता के उपयोग में वृद्धि करने की जरूरत है। टीआईईएस के तहत सहायता प्राप्त नहीं करने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भारत का एक-तिहाई वाणिज्यिक निर्यात करते हैं। स्पष्ट रूप से राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को व्यापार के अनुकूल अवसंरचना में वृद्धि के लिए टीआईईएस के तहत और अधिक सहायता लेने की जरूरत है।

एसपीएस संबंधित अवसंरचना

पर्याप्त शोध संस्थानों और एनएबीएल अधिमान्य प्रयोगशालाओं की मौजूदगी अंतरराष्ट्रीय मानकों[4] के अनुरूप उत्पादों की गुणवत्ता में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। विशेष रूप से कृषि निर्यात के संवर्धन के लिए परीक्षण और प्रमाणन अवसंरचना की जरूरत है, जिसे विनियमित बाजारों में गैर आनुपातिक उच्च गैर-शुल्क अवरोधों का सामना करना पड़ता है। तथापि, राज्यों में एनएबीएल अधिमान्य प्रयोगशालाओं की संख्या में काफी असमानता है। राष्ट्रीय प्रमाणन निकाय अधिमान्यता बोर्ड

[1]मूलभूत सड़क सांख्यिकी 2017-18, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
[2]सीआईआई और आर्थर डी लिटिल (2020), रीइमेजिनिंग इंडियाज सप्लाइ चेन: ए बोल्ड विजन फॉर 2030
[3]आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21
[4]निर्यात तत्परता सूचकांक, नीति आयोग

द्वारा अधिमान्य निरीक्षण एजेंसियां भी केवल 14 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में उपलब्ध हैं।

कई राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों जहां परीक्षण और प्रमाणन की पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं, उनमें एसपीएस का सामना करने वाली वस्तुओं के कारोबार की प्रचुर संभावना है। उदाहरण के लिए, पूर्वोत्तर क्षेत्र में अच्छी कृषि जलवायु परिस्थितियां हैं और मसाले, जैविक या अजैविक उत्पाद, अदरक और काली मिर्च जैसे उत्पाद उगाए तथा इस क्षेत्र से आसानी से निर्यात किए जा सकते हैं। लेकिन पर्याप्त परीक्षण और प्रमाणन प्रयोगशालाओं का अभाव व्यापारिक अकुशलता और अवरोध निर्मित करता है। वर्तमान में पूर्वोत्तर से कई कृषि उत्पाद परीक्षण के लिए कोलकाता भेजे जाते हैं जिनमें समय लगता है और लागत भी बढ़ती है। स्पष्ट रूप से, देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र[5] में अधिक एनएबीएल–अधिमान्य खाद्य प्रयोगशालाओं को स्थापित करने की जरूरत है।

भंडारण क्षमता

समुचित भंडारण और शीत भंडारण (कोल्ड स्टोरेज) क्षमता भी निर्यात संवर्धन के लिए महत्त्वपूर्ण होगी। शीत भंडारण का वितरण भी अत्यधिक असमान है। अभी 31 अगस्त, 2020 की स्थिति में करीब 71.6% शीत भंडारण क्षमता उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात और पंजाब में केंद्रित है। अन्य राज्यों के साथ झारखंड, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ जैसे कई राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में केंद्र सरकार से सहायता प्राप्त योजना जैसे प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत क्रियान्वित (या क्रियान्वयन अधीन) शीत भंडारण परियोजनाओं की संख्या भी बहुत कम[6] है।

व्यापार के अनुकूल अवसंरचना के विकास के लिए उपलब्ध सहायता सुविधाओं के उपयोग में राज्यों को अधिक सक्रियता दिखाने की जरूरत है। बेहतर भंडारण और आधुनिक शीत भंडारण श्रृंखला सहित कृषि सुविधाओं के विकास के लिए हाल में घोषित एक लाख करोड़ रुपये की विशेष निधि का लाभ उठाने के लिए राज्यों को भी निर्यातकों को सहायता करनी चाहिए। बंदरगाहों पर शीत भंडारण सुविधाएं उपज के नुकसान को कम करने में महत्त्वपूर्ण होंगी। वर्तमान में शीत भंडारण में बंदरगाहों का योगदान[7] 2% है। कुछ विमानतल अपने यहां शीत भंडारण सुविधाओं में वृद्धि कर रहे हैं। हाल फिलहाल में दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरू जैसे विमानतलों ने शीत भंडारण सुविधाओं में काफी वृद्धि की है लेकिन छोटे विमानतलों की क्षमता अपर्याप्त है।

सूचना वितरण अवसंरचना

राज्य स्तर पर निर्यात के लिए विभिन्न गुणवत्ता और मानक अपेक्षाओं के संबंध में अहम सूचनाओं के प्रसार के लिए ऑनलाइन पोर्टल और व्यापारिक मार्गदर्शिका जैसी अन्य सॉफ्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर की जरूरत भी है। कई निर्यात गंतव्यों में उत्पाद से जुड़ी विशिष्टताओं का पालन करने की जरूरत होती है और यह सुनिश्चित करना निर्यातकों की जिम्मेदारी होती है कि उनके उत्पाद इन मानकों पर खरे उतरते हों। प्रमुख निर्यात बाजारों में मानकों और नियमों से संबंधित सूचनाओं का प्रसार और एमएसएमई को इन अर्हताओं के पालन में मार्गदर्शन देना राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की निर्यात रणनीति का मुख्य सिद्धांत होना चाहिए। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को भी फर्मों को निर्यात के मकसद से उनके उत्पादों के परीक्षण और/या प्रमाणन में सहायता करनी चाहिए। निर्यात तत्परता सूचकांक पर रिपोर्ट के अनुसार केवल 10 राज्यों ने व्यापार मार्गदर्शिका तैयार की है और केवल 15 राज्यों में निर्यातकों के लिए ऑनलाइन पोर्टल हैं।

निर्यात संवर्धन के लिए औद्योगिक क्लस्टर

वैश्विक मूल्य श्रृंखला में राज्य के बेहतर एकीकरण को सुगम बनाने के लिए सक्षम औद्योगिक क्लस्टर विकसित करने की जरूरत है। मौजूदा क्लस्टरों की मौजूदा स्थिति की समीक्षा और क्षमता निर्माण कवायद के उद्देश्य से राज्यों को पहले से विद्यमान क्लस्टरों के निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए एक तंत्र विकसित करने की जरूरत है। इस प्रकार के मूल्यांकन में अवसंरचना में व्याप्त समस्याओं के साथ ही प्रौद्योगिकी उन्नयन में चुनौतियां, कुशल मानव संसाधनों तक पहुंच, पर्यावरणीय निरंतरता आदि से संबंधित पहलुओं को शामिल किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार राज्यों द्वारा इस प्रकार के क्लस्टरों के मूल्यांकन को वित्तीय सहायता के माध्यम से प्रोत्साहित कर सकती है।

लॉजिस्टिक्स और भंडारण संबंधी नीति

लॉजिस्टिक और भंडारण के लिए राज्य का नीतिगत फ्रेमवर्क तैयार करने और उसे क्रियान्वित करने पर जोर दिए जाने की जरूरत है। मई 2020 की स्थिति में देश के 8 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की स्वतंत्र लॉजिस्टिक और भंडारण नीति है। केंद्र, इस तरह की नीति बनाने में न केवल राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों का मार्गदर्शन कर सकता है, बल्कि विभिन्न नीतियों में प्रमुख पहलुओं को एक समान बनाने में भी मदद कर सकता है। इससे लॉजिस्टिक्स और भंडारण संबंधी राज्यस्तरीय नीति निर्धारण की प्रक्रिया में तेजी आएगी।

अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) अवसंरचना

मूल्य वर्धित निर्यातों के संवर्धन में अनुसंधान संस्थानों और एनएबीएल अधिमान्य प्रयोगशालाओं की महत्त्वपूर्ण भूमिका होगी। वर्तमान में अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) को प्रोत्साहित करने में सरकारी सहायता लगभग संपूर्ण रूप से केंद्र सरकार द्वारा वहन की जाती है, जबकि आर एंड डी व्यय को बढ़ाने में राज्य सरकारों की भागीदारी सीमित है। इस प्रकार से स्थानीय आर एंड डी संस्थानों में राज्य सरकारों की ओर से अधिक निवेश करने की जरूरत है। राज्यों को उपयुक्त प्रोत्साहन ढांचे के माध्यम से फर्मों को अधिक अनुसंधान गतिविधियों को अपनाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ■

[5]आईबिड
[6]खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार
[7]कोल्डचेन रिपोर्ट 2021, लॉजिस्टिक्स इनसाइडर

कारोबारी आंकड़ों की गलत रिपोर्टिंग और अनौपचारिक पूंजी प्रवाह – आकलन, कारण और समाधान

भारत में व्यापार संबंधी आंकड़े जिस तरह रिपोर्ट किए जाते हैं, उनमें सामान्य तौर पर भारत के व्यापार साझीदारों द्वारा रिपोर्ट किए जाने वाले परिवहन और ट्रांजैक्शन लागतों सहित अन्य आंकड़ों से किंचित विसंगति रहती है। इस बात को मार्जित, दासगुप्ता और मित्रा द्वारा भारतीय संदर्भ में अपने शोध पत्र में सबसे पहले (2000) में उठाया गया था। इसमें कहा गया कि आर्थिक सुधारों के बाद रुपये के अवमूल्यन से हो सकता है कि निर्यात आय में शुरुआती तौर पर वृद्धि रिपोर्ट की गई हो, क्योंकि कालाबाजारी प्रीमियम कम हो गया था। लेकिन रिपोर्ट की गई यह वृद्धि निर्यातों की वास्तविक मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि को परिलक्षित नहीं करती। लिहाजा, आधिकारिक आंकड़ों को सही करने की जरूरत है। इस संबंध में बहुत कुछ लिखा जाता रहा है, लेकिन दुर्भाग्य से भारत में भारतीय विद्वानों ने इस पर बहुत कम विचार किया और वैश्विक पटल पर मुख्य तौर पर चीन के संदर्भ में यह काफी अधिक रहा।

व्यापारिक लेन–देन का इस प्रकार गलत रिपोर्ट किया जाना, अलिखित या अनौपचारिक पूंजी प्रवाह को परिलक्षित करता है। तथापि, इस प्रकार के पूंजी प्रवाह के व्यापारिक चैनल से स्वतंत्र अन्य चैनल भी विद्यमान हो सकते हैं। दुर्भाग्य से अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ), विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन (अंकटाड) आदि जैसे विश्व संगठन भी दीर्घकालिक पूंजी प्रवाह का वास्तविक आंकड़ा प्रदान नहीं करते। यहां तक कि सुशासन संबंधी मान्य आंकड़े भी इस अलिखित पूंजी प्रवाह के स्रोत को स्पष्ट नहीं करते।

समग्र स्तर पर देखा जाए तो देश के भीतर या बाहर अलिखित पूंजी प्रवाह न केवल व्यापार क्षेत्र से, बल्कि विभिन्न चैनलों से प्रभावित होता है। ऐसे चैनल, जिनके माध्यम से मुद्रा परिवर्तित होती है और उसका वैश्विक लेन–देन होता है। वास्तविक आंकड़ों के विश्लेषण पर अब तक संपूर्ण दस्तावेज एकमात्र व्यापार क्षेत्र के लेन–देन पर जोर देते हैं, क्योंकि आयात–निर्यात का वास्तविक आंकड़ा दीर्घावधि के लिए उपलब्ध है। लेकिन इसमें एक महत्त्वपूर्ण पहलू छूट जाता है, जो किसी भी अर्थव्यवस्था में गैर–व्यापारिक क्षेत्र से संबंधित है। फल–फूल रहा गैर–व्यापारिक क्षेत्र अवैध चैनलों के माध्यम से पूंजी प्रवाह को भीतर ला और बाहर भेज सकता है। कई बार अलिखित प्रवाह को जानने के लिए व्यापारिक खातों के लेन–देन पर बहुत अधिक जोर नहीं दिया जाना चाहिए।

स्थिति का सूक्ष्म आकलन व्यापारियों और हितधारकों के भौतिक सर्वेक्षण के माध्यम से किया गया। चमड़ा, खिलौने, पेट्रो रसायन, विभिन्न सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई), हस्तशिल्प, सौंदर्य प्रसाधन, तांबा और कृषि उद्योग से संबंधित व्यापारियों के साक्षात्कार द्वारा जमीनी स्तर का सर्वेक्षण किया गया।

*यह आलेख प्रफेसर सुगता मार्जित के शोध अध्ययन पर आधारित है, जिसके लिए इंडिया एक्ज़िम बैंक द्वारा सहयोग दिया गया है।

साक्षात्कारदाताओं के अनुसार, आंकड़ों के बेमेल/कम बताने के पीछे सामान्य कारण भ्रष्ट कारोबारियों द्वारा सीमा शुल्क अधिकारियों को रिश्वत देकर निर्यातों और आयातों को ओवर–इनवॉयस यानी अधिक बिल बनवा लेना या अंडर–इनवॉयस यानी मूल्य से कम राशि का बिल बनवा लेना था, ताकि वे अपने कर बचा सकें, सरकार से प्रोत्साहन हासिल कर सकें सीमा शुल्क बचाने के लिए हवाला एजेंट के रूप में काम कर सकें। इसे एक उदाहरण के जरिए समझा जा सकता है। श्री ए. किसी प्रतिष्ठित कार कंपनी के कार इंजन और कार का कोई विशिष्ट ब्रांड आयात करते हैं। कंपनी का आधिकारिक मूल्य 5000 यूएस डॉलर है। इस पर लगभग 50% का शुल्क लगता है। ऐसे में श्री ए. 2000 यूएस डॉलर का एक लोकल इनवॉयस बनाते हैं और कर का भुगतान करने के लिए और इंजन को मंजूरी दिलाने के लिए इसे मुंबई कस्टम्स को प्रस्तुत करते हैं। कोई अधिकारी कुछ घूस लेकर इसे मंजूरी देने पर राजी हो सकता है। लेकिन चूंकि यह दस्तावेज ऑनलाइन लिस्ट किया जाएगा, तो यह विभिन्न जगहों पर दूसरे अधिकारियों को भी दिखाई देगा। मूल्यांकनकर्ता के रूप में बैठे अधिकारी कार कंपनी, उसके इंजन और उनके सही मूल्य की जानकारी रखते हैं। तो जब यह दस्तावेज ऑनलाइन लिस्ट किया जाएगा, तो वे अधिकारी इसे पकड़ लेंगे और गलत घोषणा देने पर यह काम अटक जाएगा। मूल्यांकनकर्ता इस पर सही मूल्य डालेंगे और यदि श्री ए. अपने इंजन को मंजूरी दिलाना चाहते हैं, तो उन्हें उस मूल्य पर शुल्क का भुगतान करना होगा।

कुछ साक्षात्कारदाताओं के अनुसार, गलत रिपोर्टिंग का कारण अदृश्य निर्यात/आयात, यूरोपीय संघ से इतर किसी देश का निर्यात/आयात अथवा फर्जी या फिलर निर्यात/आयात हो सकता है। अगर कंटेनरों की कभी घोषणा ही न की जाए तो यह भ्रष्टाचार के दायरे में आता है और इस प्रकार यह अदृश्य निर्यात या आयात का मामला बन जाता है। ऐसे मामलों मे, सीमा शुल्क कार्यालय में कोई इनवॉयस प्रस्तुत ही नहीं किया जाता, केवल संबंधित अधिकारी और बंदरगाह पर तैनात सुरक्षा अधिकारी को रिश्वत दे दी जाती है। इसलिए जब ये अघोषित कंटेनर उस सीमा शुल्क अधिकारी के पास आते हैं तो वह उसे बिना किसी को खबर किए मंजूरी दे देता है। यह तरीका बहुत खतरनाक है और किसी भी देश को क्षति पहुंचा सकता है। क्योंकि ऐसे कंटेनरों में ड्रग्स से लेकर सोना, अवैध हथियार तक कुछ भी हो सकता है, जो गलत तरीके से देश में पहुंच सकता है। हालांकि अब इस तरह के काम करना कठिन होता जा रहा है, क्योंकि कंटेनरों को शिपमेंट के दौरान हमेशा बारकोड लगाए जाने लगे हैं और हर कंटेनर की वास्तविक स्थिति किसी भी समय ट्रैक की जा सकती है। हालांकि इस तरह के मामलों में हवाला का पैसा इधर–उधर होता रहता है।

जब साक्षात्कारदाताओं से गलत रिपोर्टिंग के कारणों के संबंध में पूछा गया, तो उन्होंने विनियमन, कर संबंधी कारणों, विलंब आदि को मुख्य मुद्दा बताया। एक बार जब निर्यातक/आयातक विदेश से कोई ऑर्डर देता है तो विक्रेता को सामान्य तौर पर माल/कंसाइनमेंट जहाज से भेजने में दो से तीन महीने का समय लगता है। कोविड जैसे हालात भी हो सकते हैं, जिससे सरकार को कुछ वस्तुओं के निर्यात/आयात को प्रतिबंधित करने के लिए बाध्य होना पड़ा। आयातक/निर्यातक ऑर्डर देने के समय इससे अनभिज्ञ हो सकते हैं। इससे ऐसा मामला हो सकता है कि कारोबारी निर्यात/आयात के लिए प्रतिबंधित एचएस कोड्स को ऐसे कोड में बदलने के लिए दबाव या हथकंडे अपनाएं जो प्रतिबंधित नहीं हैं और इस प्रकार उन पर शुल्क भी अलग होगा।

साक्षात्कारदाताओं से इस बारे में भी पूछा गया कि क्या यह संभव है कि निर्यात आय का एक हिस्सा आयातित सामग्री को वित्त प्रदान करने के लिए विदेश में रोक दिया गया हो? इस पर बाद में गोपनीय रूप से जवाब दिया गया कि यह बिल्कुल संभव है। लेकिन यह ज्यादातर अल्प अवधि के लिए है। अल्प अवधि (एक साल) के लिए यह कृत्य वैधानिक है, जहां एक साल का मौजूदा प्रावधान काफी है और सरकार को इसको बढ़ाना नहीं चाहिए। यह कम कर वाले देशों (टैक्स हैवंस) में भी हो सकता है। उन देशों में बैंक खाता खोलना बहुत आसान है और यदि किसी व्यक्ति के पास बहुत अधिक धन है तो वह खाता खोल सकता है और/अथवा वहां की नागरिकता भी ले सकता है या अपने परिवार के किसी सदस्य को इन देशों में रख सकता है। साक्षात्कारदाताओं ने अपनी पहचान गोपनीय बनाए रखते हुए बताया कि अवैध धन विदेशों में हमेशा व्यापार की गलत सूचनाओं के माध्यम से भेजा जाता है। उन्होंने विस्तारपूर्वक बताया कि पीतल और तांबे की सामग्री में सरकार बिल मूल्य का 10% ड्यूटी ड्रॉबैक के रूप में प्रोत्साहन प्रदान करती है। इसमें निर्यातक अधिक भार दिखाकर और उसके अनुसार मूल्य में वृद्धि कर देगा जिससे उसे सरकार से अधिक प्रोत्साहन प्राप्त होगा। तथापि इसके लिए निर्यातक और माल के वजन की जांच करने वाले सीमा शुल्क अधिकारी के बीच में मिलीभगत की जरूरत होगी। व्यापारी की विदेश में क्रेता/विक्रेता से भी मिलीभगत होगी, ताकि वे अधिक राशि का बिल भेज सकें, जो बैंक के माध्यम से भेजा जाना चाहिए। बढ़ी हुई राशि को वह वापस कैसे हासिल करता है, यह अलग कहानी है। यह हवाला के जरिए की जा सकती है।

निर्यात और आयात को गलत सूचित करने के परंपरागत चैनलों के अलावा ऐसे रास्ते हैं जिनसे लोग माल का अवैध निर्यात और आयात करते हैं, जो देश के लिए अच्छा नहीं है। इसमें बहुत बड़े स्तर पर काला धन पैदा होता है और परिणामत: बड़ी धन राशि बाहर जाती है। सोने, नशीली दवाओं और हथियारों की तस्करी अब भारत में प्रमुख अवैध व्यापार माध्यम हैं। एक अन्य प्रकार की व्यापार पद्धति है जो कि बेहिसाब धन और काला धन के साथ की जाती है। इस प्रकार के मामले में निर्यातक कुरियर या पोस्ट पार्सल सेवा के माध्यम से कम मात्रा में माल भेजता है और इसे मुफ्त नमूने के तौर पर दर्शाता है। कोई निर्यात माल प्रेषण दस्तावेज इन मामलों में प्रोसेस नहीं किया जाता, क्योंकि इन्हें निर्यात की श्रेणी में नहीं रखा जाता। कुरियर एजेंट द्वारा सीमा शुल्क अधिकारियों को बिल प्रस्तुत किया जाता है और बिल में दर्शाया जाता है कि माल केवल नमूने हैं तथा उनका कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है। तथापि, प्राप्तकर्ता माल बेच देता है और हवाला के माध्यम से भुगतान का प्रबंध करता है। इस प्रकार के संचालन की कीमत लाखों में होती है। इसके माध्यम से बहुत बड़ी मात्रा में काम होता है और फिर से समुचित आंकड़े प्राप्त करना कठिन होता है, क्योंकि देश से नियमित रूप से बहुत अधिक माल बाहर जाता है जिनमें से कई वास्तविक नमूने भी होते हैं।

इसका सार और नतीजे यह बताते हैं कि यह महत्त्वपूर्ण है कि सरकारों को अलिखित पूंजी प्रवाह जो कि दोनों व्यापारिक और गैर व्यापारिक क्षेत्रों में उत्पन्न हो सकता है, उसके रुझान की निगरानी के लिए लेन-देन के दोनों छोर पर आधिकारिक वास्तविक आंकड़े रखने के उद्देश्य से द्विपक्षीय पहल करनी चाहिए। इससे न केवल राजस्व आकलन को बेहतर करने में मदद मिलेगी, बल्कि राष्ट्रीय आय के आंकड़ों के संबंध में बेहतर सूचना प्राप्त करने में भी सहायता मिलेगी।

यह अध्ययन धारणाओं की जानकारी देता है और नीतिगत खामियों के संबंध में वास्तविक व्यापारियों के अनुभव नियामक प्राधिकारियों के लिए दिशानिर्देशों का काम करते हैं। सामान्य तौर पर कहें तो चेन्नई को छोड़कर बड़े शहरों के व्यापारियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार गलत सूचना देने की घटनाएं कुल कारोबार का करीब 5% से 10% है, जो समग्र प्रमाण की पुष्टि करता है। चेन्नई का प्रकरण विसंगति का मामला है। या तो यह वास्तविकता का विशुद्ध क्षेत्रीय अंतर है या फिर समस्या को बताने वाला सच है। जैसा कि हमारा रिकॉर्ड बताता है कि भारत-सिंगापुर व्यापार में अन्य देशों से अलग रुझान हैं, जिसकी गंभीरता से जांच करने की जरूरत है।

दूसरा, अध्ययन से पता चलता है कि यह निर्यात की गलत रिपोर्टिंग है, जो आयात की भी गलत रिपोर्टिंग का कारण बनती है। कोई इसे आयात का वित्तीय मसला और भारतीयों द्वारा अलिखित विदेशी निवेश भी कह सकता है। ऐसे में, निर्यात मोर्चे पर कमी का पता लगाने के लिए स्पष्ट दिशानिर्देशों की जरूरत है। तुलनात्मक ब्याज दरों में अंतर और मुद्रा के प्रत्याशित अवमूल्यन इस प्रकार के प्रोत्साहनों को प्रभावित करेंगे।

तीसरा, व्यापार संतुलन या भुगतान संतुलन एक संवेदनशील विषय है और जीडीपी में विदेश व्यापार का बहुत योगदान रहता है। यह उसी प्रकार की समस्या है, जैसे राष्ट्रीय आय में अनौपचारिक क्षेत्र के योगदान के लिए लेखांकन की है।

अंत में, यदि सरकार कम से कम प्रमुख व्यापारिक भागीदारों के साथ द्विपक्षीय माध्यमों के द्वारा वास्तविक डेटाबेस विकसित करे तो बहुत लाभ होगा। इससे व्यापारिक और मैक्रो आंकड़ों के पूर्वानुमान में मदद मिलेगी। दुर्भाग्य से, ज्यादातर देशों में ऐसा नहीं है। लेकिन यह 'अलिखित' पूंजी प्रवाहों का पता लगाने में संवेदनशील प्रतीत होता है। ■

सेमीकंडक्टर की वैश्विक कमी

सेमीकंडक्टर्स ऐसे भौतिक पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और उपकरणों में करंट के प्रवाह का प्रबंधन और नियंत्रण करने के लिए बनाए गए हैं। ये सामान्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक चिप्स, कंप्यूटिंग घटक और डिवाइस, संचार के उन्नत साधनों, कंप्यूटिंग, स्वास्थ्य सेवाओं, सैन्य प्रणाली, परिवहन, स्वच्छ ऊर्जा, और विभिन्न अन्य एप्लीकेशनों के विकास में उपयोग किए जाते हैं। ये विशुद्ध तत्त्वों, विशेषकर सिलिकॉन या जर्मेनियम या गैलियम आर्सेनाइड जैसे मिश्रण से बनाए जाते हैं। डिजाइन और निर्माण के लिए सेमीकंडक्टर जटिल उत्पाद हैं तथा इनकी उच्च विशेषीकृत वैश्विक मूल्य श्रृंखला है।

विशिष्टिकरण आधार पर सेमीकंडक्टर कंपनियां या तो एकीकृत डिवाइस निर्माता (आईडीएम), फैब्लेस (हार्डवेयर डिजाइन बेचने वाली कंपनियां जो हार्डवेयर विनिर्माण किसी अन्य भागीदार को आउटसोर्स करने वाली कंपनी) आपूर्तिकर्ता या फांउड्री इकाई हो सकती हैं। आईडीएम एकीकृत सर्किट उत्पादों की डिजाइन के साथ ही उनका विक्रय करती हैं। फैब्लेस आपूर्तिकर्ता की चिप्स की डिजाइन और फैब्रिकेशन की आउटसोर्सिंग में विशेषज्ञता है और फाउंड्री की एकीकृत सर्किट के फैब्रिकेशन या विनिर्माण में विशेषज्ञता है।

सेमीकंडक्टरों का वैश्विक बाजार

ज्यादातर आर एंड डी (अनुसंधान और विकास) गतिविधियों जैसे ईडीए और कोर आईपी, चिप डिजाइन और उपकरण विनिर्माण में अमेरिका अग्रणी है। जबकि जापान, दक्षिण कोरिया और ताइवान जैसे पूर्व एशिया के देशों ने विनिर्माण गतिविधियों में अपने को प्रतिस्पर्धा में आगे बना कर रखा है। विश्व की कुल विनिर्माण क्षमता का 75% इसी क्षेत्र में केंद्रित है।

उल्लेखनीय है कि ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन (टीएसएमसी) दुनिया की सबसे बड़ी कांट्रैक्ट चिप विनिर्माता कंपनी है जिसके पास चिप विनिर्माण के फाउंड्री कारोबार का 54% है। पूर्व एशिया, विशेषकर जापान महत्त्वपूर्ण सामग्री का प्रमुख आपूर्तिकर्ता है। जहां तक असेंबली, पैकेजिंग और परीक्षण सेवाओं का सवाल है, चीन दुनिया में अग्रणी है।

गतिविधि और क्षेत्र द्वारा मूल्यवर्धित सेमीकंडक्टर उद्योग, 2019 (%)

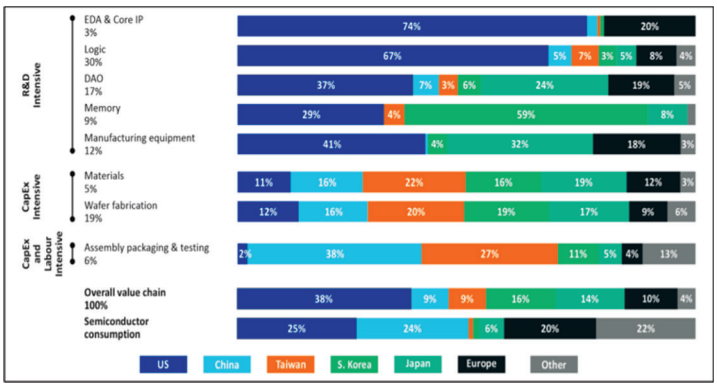

स्रोत: सेमीकंडक्टर एसोसिएशन से लिए गए अनुसार

कुल सेमीकंडक्टर बाजार में 2020 में इंटेल 15.6% बाजार हिस्सेदारी के साथ अव्वल रहा। उसके बाद सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स (12.4%), एसके हायनिक्स (5.5%) और माइक्रो टेक्नोलॉजी (4.7%) का स्थान रहा। इसके अतिरिक्त, 2020 में सेमीकंडक्टर की मांग कंप्यूटर क्षेत्र में सबसे अधिक (32%) और इसके बाद संचार में (31%), औद्योगिक उपयोग (12%) और उपभोक्ता उपयोग (12%) जैसे क्षेत्रों में रही।

सेमीकंडक्टर कारोबार

कच्चा तेल, परिशोधित तेल और कारों के बाद सेमीकंडक्टर दुनिया में चौथा सबसे अधिक व्यापार वाला उत्पाद है। साल 2020 में सेमीकंडक्टर का वैश्विक निर्यात 783.9 बिलियन यूएस डॉलर के बराबर था और 2011 से 2020 के दौरान 7.5% की एएजीआर दर्ज की गई थी।

सेमीकंडक्टर और विनिर्माताओं के लिए भंडारण का केंद्र हांगकांग 2020 में सेमीकंडक्टर का सबसे बड़ा निर्यातक रहा। अभी हाल तक उसे अमेरिका से विशेष दर्जे के अंतर्गत प्राथमिकता की वरीयता हासिल थी। साल 2020 में अन्य शीर्ष

टेबल 1: सेमिकंडक्टरों के शीर्ष निर्यातक और आयातक

निर्यात				आयात			
रैंक	देश	मूल्य (बिलियन यूएस डॉलर में)	विश्व निर्यात में हिस्सेदारी	रैंक	देश	मूल्य (बिलियन यूएस डॉलर में)	विश्व निर्यात में हिस्सेदारी
1	हांगकांग	153.9	20%	1	चीन	350.8	37%
2	ताइवान	122.9	16%	2	हांगकांग	168.9	18%
3	चीन	117.1	15%	3	सिंगापुर	71.7	8%
4	सिंगापुर	86.3	11%	4	ताइवान	62.6	7%
5	दक्षिण कोरिया	82.9	11%	5	दक्षिण कोरिया	40.3	4%
6	मलेशिया	49.3	6%	6	वियतनाम	39.1	4%
7	यूएसए	44.2	6%	7	मलेशिया	33.4	4%
8	जापान	28.9	4%	8	यूएसए	31.9	3%
9	फिलिपींस	20.2	3%	9	जापान	18.8	2%
10	वियतनाम	14.0	2%	10	मेक्सिको	18.7	2%
31	**भारत**	**0.3**	**0%**	**15**	**भारत**	**8.4**	**1%**

स्रोत : आईटीसी ट्रेड मैप, इंडिया एक्ज़िम बैंक अनुसंधान

निर्यातकों में ताइवान, चीन, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया शामिल रहे, जो असेंबली और विनिर्माण के केंद्र थे। चीन का विशालकाय इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग उसे दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर आयातक बनाता है। उसके बाद हांगकांग, सिंगापुर, ताइवान और दक्षिण कोरिया का नंबर आता है।

सेमीकंडक्टरों की कमी

दुनियाभर में इलेक्ट्रॉनिक्स, मोटर और कई अन्य उद्योगों में इस्तेमाल किए जाने वाले सेमीकंडक्टरों की हाल के दौर में कमी देखी गई। इसके कई कारण हैं। इस कमी की जड़ को कोविड महामारी की शुरुआत से जोड़ा जा सकता है। महामारी के कारण दुनिया भर में लॉकडाउन लागू करना पड़ा जिससे कई अहम चिप निर्माता इकाइयों

का काम ठप हो गया। एक तरफ जहां आपूर्ति रुक गई, वहीं दूसरी तरफ चिप की जरूरत वाले सभी तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की मांग अप्रत्याशित रूप से बढ़ी। उल्लेखनीय है कि एक चिप को बनाने में तीन महीने से अधिक समय लग सकता है। ऐसे में अल्प सूचना पर आपूर्ति नहीं बढ़ाई जा सकती थी।

इसके अतिरिक्त, 2019 और 2020 में अमेरिका द्वारा लागू किए गए निर्यात नियंत्रण उपायों ने हुआवे और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंटरनेशनल कॉरपोरेशन के साथ ही चीनी फर्मों के साथ सहयोग करने वाली वैश्विक फाउंड्री इकाइयों की अमेरिका निर्मित सेमीकंडक्टर उत्पादन उपकरणों और सॉफ्टवेयर तक पहुंच को रोक दिया। ऐसे परिदृश्य में समय से डिलीवरी के अपने मॉडल और इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार को आपूर्ति बढ़ने के कारण ऑटोमोबाइल निर्माता सबसे अधिक प्रभावित हुए। इस बीच चिप फैक्ट्री की 10 से 15 बिलियन यूएस डॉलर की लागत को देखते हुए क्षमता निर्माण में कई साल लग सकते हैं। ऐसे में 2023 तक आपूर्ति में दिक्कत बनी रह सकती है।

भारत के ऑटोमोबाइल उद्योग पर असर

सेमीकंडक्टर की वैश्विक कमी का भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग पर असर होना शुरू हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक कलपुर्जों की कमी के परिणामस्वरूप ऑटो उद्योग में 4.5-5 लाख बुकिंग लंबित हैं। अग्रणी निर्माता मारुति सुजुकी ने सितंबर 2021 में अपने उत्पादन में 60% की कटौती कर दी है। इसी प्रकार, महिंद्रा एंड महिंद्रा ने सितंबर में अपने उत्पादन में 20-25% की कमी कर दी है और इसी महीने में सात दिनों के लिए उत्पादन बंद कर दिया। निसान, ह्युंडै और एमजी मोटर जैसी अन्य कंपनियों ने भी उत्पादन में कटौती की है।

भारत में यात्री कारों की बिक्री (हजार इकाई में)

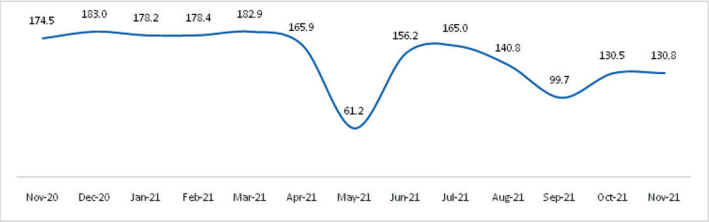

स्रोत: आईटीसी ट्रेड मैप, इंडिया एक्जिम बैंक अनुसंधान

यह भी उल्लेखनीय है कि इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) श्रेणी भी प्रभावित हुई है, जहां बताया गया है कि टाटा मोटर्स में ईवी मॉडल पर प्रतीक्षा अवधि छह महीने की हो गई है। क्रिसिल रेटिंग्स के अनुसार सेमीकंडक्टर की विश्वव्यापी कमी से इस वित्तीय वर्ष में यात्री वाहनों की बिक्री में भारत की वृद्धि को 11-13% तक कमी आएगी। यह कमी न होने पर हो सकने वाली दर से 4-6% कम है।

भारत का सेमीकंडक्टर बाजार

भारत की विशिष्टता माइक्रो प्रोसेसर्स, मेमरी सबसिस्टम्स और एनालॉग चिप डिजाइन में है। परिणामस्वरूप, देश में विनिर्माण गतिविधियों के अभाव में वर्तमान में भारत की सेमीकंडक्टर की पूरी मांग आयात के माध्यम से पूरी होती है। इस प्रकार, यह उद्योग जिन चुनौतियों का सामना कर रहा है उनमें शामिल है :

- **सेमीकंडक्टर के आयात पर शून्य मूलभूत सीमा शुल्क:** सेमीकंडक्टर, सूचना प्रौद्योगिकी करार (आईटीए-1) का हिस्सा हैं, इसलिए इन पर शून्य मूलभूत सीमा शुल्क होने से देश में सेमीकंडक्टर विनिर्माण पर प्रोत्साहन कम है।
- **विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धी क्षमता की स्थापना के लिए पूंजी लागत का अत्यधिक होना:** चिप फैक्ट्री की स्थापना में बहुत अधिक निवेश की जरूरत के कारण भारत में पूंजी की अत्यधिक लागत को देखते हुए घरेलू निर्माताओं के लिए इसकी स्थापना वित्तीय रूप से व्यवहारिक नहीं है।
- **बिजली और पानी की भरोसेमंद आपूर्ति जैसी सहायक अवसंरचना की अपर्याप्तता:** सेमीकंडक्टर चिप फैक्ट्री को निरंतर बिजली और पानी की जरूरत होती है। यदि यह प्रभावित होती है, तो इसके उत्पादन की लागत बढ़ जाती है।
- **उच्च ढुलाई लागत:** भारत ने जहां लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक में हाल के वर्षों में अत्यधिक सुधार दर्शाया है, वहीं यह अब भी कई देशों से पीछे है और क्रम में 40 से भी ऊपर है।

आगे की राह: भारतीय सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए अवसर

सेमीकंडक्टर की कमी ने देशों के सेमीकंडक्टर के निर्माण के लिए कुछ एक देशों पर अत्यधिक निर्भरता को उजागर कर दिया है, खासकर ताइवान पर। इस संकट से मुकाबले के लिए कई देशों ने सेमीकंडक्टर के घरेलू उत्पादन का विस्तार करने की योजनाओं की घोषणा की है। उदाहरण के लिए, अमेरिका ने अपने अवसंरचना निवेश पैकेज में सेमीकंडक्टर के उत्पादन और अनुसंधान के लिए 50 बिलियन यूएस डॉलर आवंटित किए हैं।

भारत भी जून-जुलाई 2022 तक देश में पहली सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाई की स्थापना के लिए तैयारी कर रहा है। भारत ने कंपोनेंट्स और सेमीकंडक्टर विनिर्माण संवर्धन योजना (एसपीईसीएस) भी बनाई है। योजना का लक्ष्य कोर कलपुर्जों के विकास के लिए क्षमता विकास को गति देकर और प्रोत्साहित कर भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग का वैश्विक केंद्र बनाना है। हाल में, दिसंबर 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के लिए 76,000 करोड़ रुपये के नीतिगत समर्थन को मंजूरी दी है। भारत में सेमीकंडक्टर फैब्स और डिसप्ले फैब्स की स्थापना के लिए योजना में पात्र आवेदकों को परियोजना लागत की 50% तक वित्तीय सहायता दी जाएगी।

पूंजीगत सहायता प्रदान करने के संबंध में सरकार ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इंटेल और एएमडी जैसे शीर्ष सेमीकंडक्टर विनिर्माताओं के साथ समन्वय के प्रयास कर रही है। टाटा समूह जैसी घरेलू कंपनियां भी सेमीकंडक्टर विनिर्माण शुरू करने की संभावनाएं तलाश रही हैं।

भारत ने पूर्व में संयंत्रों की स्थापना के लिए विनिर्माताओं को प्रोत्साहित करने की कोशिश की थी, लेकिन कोई बहुत उत्साहजनक प्रतिक्रिया नहीं मिली। निवेश प्राप्त होने के लिए निर्बाध बिजली आपूर्ति, प्रचुर पानी की आपूर्ति और निर्बाध लॉजिस्टिक्स जैसी सहायक अवसंरचना बनाना और लाभकारी प्रोत्साहन देना आवश्यक है। ■

अंतरिक्ष उद्योग

भारतीय अंतरिक्ष उद्योग: परिचय

भारतीय अंतरिक्ष उद्योग रक्षा[1] और नागरिक विमानन क्षेत्रों से मिलकर बनता है और दुनिया के कुल अंतरिक्ष उद्योग[2] का करीब 1% है। इसके अतिरिक्त, अनुमान है कि अवसंरचना में सुधार और सरकार के जोर से भारत का अंतरिक्ष और रक्षा (ए एंड डी) बाजार और गति पकड़ेगा तथा 2030 तक यह करीब 70 बिलियन यूएस डॉलर तक का हो जाएगा। इस उद्योग के कुछ महत्वपूर्ण उप-खंड हैं:

- **विमानन वायुयान:** क्षेत्रीय संपर्क के विकास में बढ़ती दिलचस्पी, पर्यटन और आकस्मिक चिकित्सा परिवहन नए अवसरों के द्वार खोल रहा है।
- **रखरखाव मरम्मत और ओवरहॉल (एमआरओ):** विमानन बेड़े के बढ़ने के साथ अधिक रखरखाव की जरूरत होगी। वर्तमान में ज्यादा एमआरओ कारोबार भारत से बाहर है।
- **संचालन और वायु यातायात प्रबंधन प्रणाली:** जीपीएस सहायित जीईओ संवर्धित संचालन (गगन) प्रणाली के आरंभ होने के साथ भारत उपग्रह आधारित संचालन प्रणालियों को क्रियान्वित करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया।

भारत में अंतरिक्ष उद्योग का विस्तार

हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) वायुयान विनिर्माण उद्योग की अग्रणी कंपनी रही है, तथापि हाल के समय में इस क्षेत्र को अन्य के लिए भी खोल दिया गया है। सितंबर 2021 में भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय ने 56 सी-295 मध्यम परिवहन विमान की खरीदी के लिए एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ करीब 20,000 करोड़ रुपये का कॉन्ट्रैक्ट किया है। यह विमान भारतीय वायु सेना के एयरो-748 विमानों की जगह लेंगे। यह एयरबस डिफेंस और टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स के बीच की संयुक्त परियोजना है। इस समझौते के तहत एयरबस डिफेंस एंड स्पेस द्वारा कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने के 48 घंटे के भीतर उड़ने के लिए तैयार 16 विमानों की आपूर्ति करेगा। शेष 4 विमान एयरबस डिफेंस एंड स्पेस और टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड (टीएएसएल) के समूह द्वारा कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने के दस साल के भीतर भारत में निर्मित किए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि यह अपनी तरह की पहली परियोजना है जिसमें निजी कंपनी द्वारा भारत में कोई सैन्य विमान बनाया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, एयरोस्पेस प्रौद्योगिकी में शोध और विकास को प्रोत्साहित करने की बढ़ती जरूरत को देखते हुए हाल में आईआईटी कानपुर और भारतीय वायु सेना ने एयरोस्पेस प्रौद्योगिकी के शैक्षणिक और शोध, दोनों क्षेत्रों में सुदृढ़ प्रौद्योगिकी के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं।

इसके अलावा रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए संभावित उत्प्रेरक के रूप में 2020 में रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (डीएपी) 2020 स्थापित की गई है। रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में 100% (74% तक स्वत: मार्ग के अंतर्गत और 74% के आगे अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत) एफडीआई के साथ घरेलू क्षेत्र के लिए इस क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने का अवसर है।

[1]इस लेख में रक्षा उद्योग के सिर्फ विमानन-विभाग को सम्मिलित किया गया है।
[2]एसोचैम (2019)

नागरिक विमानन और एमआरओ में अवसर

नागरिक विमानन

वर्तमान में भारतीय अनुसूचित एयरलाइंस द्वारा लगभग 700 विमान संचालित किए जा रहे हैं। भारतीय नागरिक विमानन क्षेत्र में इंडिगो, स्पाइसजेट, गोफर्स्ट और एयर एशिया इंडिया सहित रियायती एयरलाइंस (एलसीसी) प्रमुख हैं। इनमें से ज्यादातर एयरबस के संकरे विमान संचालित कर रही हैं। तीसरे सबसे बड़े घरेलू विमानन बाजार भारत के वित्तीय वर्ष 2025 तक घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यातायात दोनों के लिए तीसरा सबसे बड़ा बाजार बनने का अनुमान है। 2015-16 से 2019-20 तक भारत में यात्री यातायात में 11% की एएजीआर से और माल परिवहन में 6% की एएजीआर से वृद्धि हुई।

एमआरओ सेवाएं

भारत एमआरओ में क्षेत्रीय स्तर पर काम करते हुए भूटान, चीन, मलेशिया, वियतनाम आदि जैसे पड़ोसी देशों को सेवाएं प्रदान कर रहा है। एमआरओ का वैश्विक बाजार 80 बिलियन यूएस डॉलर मूल्य का है। इसमें भारत की हिस्सेदारी करीब 2.5% है। वर्तमान में भारतीय एयरलाइंस द्वारा एमआरओ सेवाओं का वार्षिक आयात लगभग 9,700 करोड़ रुपये का है जो फ्रांस, जर्मनी, जॉर्डन, मलेशिया आदि देशों से प्राप्त होती हैं। विमानन अवसंरचना के बढ़ने के साथ भारतीय एमआरओ उद्योग में खासी वृद्धि की उम्मीद है। भारतीय एयरलाइंस कंपनियां अपने राजस्व का करीब 12-15% रखरखाव पर खर्च करती हैं, जो ईंधन के बाद दूसरा सर्वाधिक लागत घटक है। भारतीय विमानन एमआरओ के 7.1% के एएजीआर से बढ़ने का अनुमान है जो 2019 में 2 बिलियन यूएस डॉलर से 2029 में 4 बिलियन यूएस डॉलर तक का हो जाएगा। इसी अवधि में वैश्विक एमआरओ के 3.5% के न्यून सीएजीआर से बढ़ने की संभावना है।

विश्व के मुकाबले तेजी से बढ़ेगा भारतीय अंतरिक्ष उद्योग

ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के अनुसार 2015-19 के दौरान वैश्विक अंतरिक्ष विनिर्माण 3% की दर से बढ़ा जबकि भारतीय विनिर्माण में 10.7% की वृद्धि दर्ज की गई। 2020 के महामारी से प्रभावित होने के बाद यह पूर्वानुमान लगाया गया है कि 2021 में दुनिया में अंतरिक्ष विनिर्माण क्षेत्र मजबूती के साथ पटरी पर लौटेगा और भारत में इसकी बहाली और अधिक मजबूती से होगी।

यह उल्लेखनीय है कि भारत पहले से ही बड़ा वाणिज्यिक और रक्षा वायुयान बाजार है। बढ़ते यात्री यातायात और सैनिक एवं रक्षा व्यय में वृद्धि के साथ वायुयानों की मांग तथा उनकी आपूर्ति श्रृंखला में बढ़ोत्तरी हो रही है।

इसके अतिरिक्त, हाल के कराधान बदलाव के साथ यह उद्योग विशेषकर एमआरओ सेवाओं के लिए एक महत्त्वपूर्ण मोड़ पर आ गया है और उम्मीद है कि भारत एमआरओ सेवाओं का केंद्र बनेगा।

समग्र रूप से भारत के अत्यधिक और बढ़ते हुए रक्षा बजट के साथ एयरोस्पेस पुर्जे और घटक के विनिर्माण में मंजूरी मार्ग से 100% एफडीआई जैसी व्यवसाय हितैषी नीतियों से भारत एयरोस्पेस विनिर्माण क्षेत्र में आने वाले वर्षों में प्रभावी वृद्धि का गवाह बन सकता है। ■

एक्ज़िम बाज़ार

समृद्ध मूल्यों और मान्यताओं को अपने में सहेजे हमारे हस्तशिल्प और हथकरघा लोगों की जड़ों, संस्कृति और अस्मिता की अनूठी अभिव्यक्ति और किसी भी देश की सबसे समृद्ध सृजनात्मक परंपरा होते हैं। शिल्पकार या दस्तकार गैर-कृषि आधारित भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। हथकरघा रोजगार की संभावनाओं से भरा श्रम-गहन क्षेत्र है।

इंडिया एक्ज़िम बैंक अपने ग्रासरूट उद्यम विकास (ग्रिड) कार्यक्रम के जरिए सामाजिक उद्यमों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, स्वयं सहायता समूहों, गैर-सरकारी संगठनों, न्यासों, सहकारी समितियों और सोसायटियों को उनके अंतरराष्ट्रीयकरण के प्रयासों में सहायता करता है। यह कार्यक्रम समाज के वंचित तबके की आजीविका संबंधी जरूरतों का समाधान करता है। साथ ही, देश के पारंपरिक दस्तकारों / ग्रामीण उद्यमियों के साथ काम करने वाले उद्यमों के लिए नए बाजार / व्यवसाय अवसर तलाशता है। ग्रिड का उद्देश्य देशभर में उत्पादक समूहों / क्लस्टरों / छोटे उद्यमों को उनके उत्पादों का सही मूल्य दिलवाने में सहायता करना और विशेष रूप से उन इकाइयों से निर्यातों को सुगम बनाना है। ग्रिड के जरिए बैंक ग्रासरूट उद्यमों / सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को उनके व्यवसाय के विभिन्न चरणों में मदद करता है। इसमें क्षमता विकास, प्रशिक्षण, निर्यात क्षमता सृजन, ग्राहक आधार का विस्तार / विविधीकरण और निर्यातों में आने वाली बाधाओं के समाधान जैसे प्रयास शामिल हैं। बैंक अपनी मार्केटिंग सलाहकारी सेवाओं (मास) के जरिए निर्यात क्षमता सृजित करने और भारतीय फर्मों के उत्पादों और सेवाओं के लिए विदेश में वितरक / खरीदार / भागीदार तलाशने में मदद करते हुए उनके वैश्वीकरण के प्रयासों में सहायता करता है।

ग्रिडमास पहलों में अन्य के साथ-साथ शिल्प उत्पादों को अग्रणी व्यापार मेलों में प्रदर्शित करना और निर्यात संवर्धन परिषद की होम एक्सपो प्रदर्शनी, कालाघोड़ा कला महोत्सव, सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय मेले सहित विभिन्न शहरों में लगने वाले कला-शिल्प मेलों में प्रदर्शित करना शामिल है। इस प्रकार की प्रदर्शनियों और व्यापार मेलों में हिस्सा लेने से ग्रासरूट दस्तकारों / उद्यमों को नए ग्राहकों तक पहुंचने में, तात्कालिक बिक्री बढ़ने, अपना ब्रांड विकसित करने और घरेलू तथा निर्यात कॉर्पोरेट ऑर्डर हासिल करने में मदद मिलती है।

विश्व व्यापार केंद्र, मुंबई में आयोजित एक्ज़िम बाज़ार 2021 का उद्घाटन समारोह, जिसमें मुख्य अतिथि के साथ हैं इडिया एक्ज़िम की प्रबंध निदेशक, उप प्रबंध निदेशक और वरिष्ठ कार्यपालक तथा एक्ज़िम बाज़ार में आए हुए दस्तकार।

बैंक के ग्रिडमास प्रयासों को और मजबूत करने के लिए बैंक ने 2017 में एक्ज़िम बाज़ार का शुभारंभ किया, जो दस्तकारों के लिए इंडिया एक्ज़िम बैंक का अनूठा मंच है। एक्ज़िम बाज़ार बैंक द्वारा सैकड़ों वर्षों से चले आ रहे पारंपरिक भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों को सहेजने और भारतीय हस्तकला की पारंपरिक विरासत के पुनरुत्थान का एक प्रयास है और यह ग्रिडमास कार्यक्रम के अंतर्गत सबसे आकर्षक और सफल शिल्प प्रदर्शनियों में से एक रहा है। अपनी शुरुआत के समय से ही एक्ज़िम बाज़ार देश के विभिन्न शहरों में आयोजित किया जाता रहा है तथा इसे स्थानीय लोगों और वहां के दस्तकारों द्वारा भी सराहा गया है। बैंक से पहले से जुड़े प्रतिभावान दस्तकारों के अलावा और भी बहुत से दस्तकारों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने में अपनी रुचि दिखाई है।

बैंक ने विश्व व्यापार केंद्र, मुंबई में 18 से 21 दिसंबर, 2021 के दौरान मुंबई में आठवां एक्ज़िम बाज़ार आयोजित किया। महाराष्ट्र के माननीय राज्यपाल, श्री भगत सिंह कोश्यारी ने एक्ज़िम बाज़ार का उद्घाटन किया। इस मौके पर इंडिया एक्ज़िम बैंक की प्रबंध निदेशक सुश्री हर्षा बंगारी और उप प्रबंध निदेशक श्री एन. रमेश विशेष रूप से उपस्थित रहे।

इस प्रदर्शनी में अन्य के साथ-साथ बिहार की मधुबनी पेंटिंग, आंध्र प्रदेश की चमड़े की कठपुतली, महाराष्ट्र की वारली पेंटिंग, राजस्थान की पिछवाई पेंटिंग, पंजाब की फुलकारी कढ़ाई, पश्चिम बंगाल की पट्टचित्र पेंटिंग, उत्तर प्रदेश के बनारसी सिल्क के कपड़े, मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग और चंदेरी बुनाई, ओडिशा की ढोकरा कला, गुजरात के अजरख टेक्सटाइल्स प्रदर्शित किए गए और बिक्री के लिए उपलब्ध रहे। एक्ज़िमम बाज़ार 2021 में एक छत के नीचे 20 राज्यों के 75 से ज़्यादा दस्तकार शामिल हुए।

ग्रासरूट उद्यम विकास और मार्केटिंग सलाहकारी सेवाएं कार्यक्रम के अंतर्गत बैंक भारत के विभिन्न जिलों से निर्यातों की संभावनाओं वाले विभिन्न उत्पादों, जैसे मुजफ्फरपुर (बिहार) की शाही लीची, कश्मीर का केसर और जालंधर से खेल वस्तुओं को चिह्नित कर भारत सरकार की 'एक ज़िला, एक उत्पादक पहल' में भी योगदान दे रहा है। ■

इंडिया एक्ज़िम बैंक की ऋण-व्यवस्थाएं

इंडिया एक्ज़िम बैंक विदेशी वित्तीय संस्थाओं, क्षेत्रीय विकास बैंकों, संप्रभु सरकारों और अन्य विदेशी संस्थाओं को ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान करता है। ये ऋण-व्यवस्थाएं उन देशों के क्रेताओं को भारत से विकासपरक तथा बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं, उपकरण, माल एवं सेवाओं का आयात करने में समर्थ बनाती हैं। इंडिया एक्ज़िम बैंक भारत सरकार के आदेश पर भी ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान करता है। इनके अंतर्गत इंडिया एक्ज़िम बैंक माल के शिपमेंट पर भारतीय निर्यातकों को कॉन्ट्रैक्ट मूल्य के 100% की प्रतिपूर्ति करता है, बशर्ते कि कुल कॉन्ट्रैक्ट मूल्य के कम से कम 75% के माल एवं सेवाओं का आयात भारत से किया गया हो। ऋण-व्यवस्थाओं के जरिए उभरते बाजारों में भारत की परियोजना निष्पादन क्षमता के प्रदर्शन में भी मदद मिली है। हाल के वर्षों में ऋण-व्यवस्थाओं ने गति पकड़ी है। विशेष रूप से अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, ओशिआनिया और सीआईएस क्षेत्रों में सबसे ज्यादा ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान की गई हैं। ऋण-व्यवस्थाओं ने भारत के राजनीतिक, रणनीतिक और वाणिज्यिक हितों को बढ़ावा देने के साथ-साथ लाभार्थी देशों में भारत की राजनीतिक ख्याति को बढ़ाने का काम भी किया है। ऋण-व्यवस्थाएं भारत की बढ़ी आर्थिक मजबूती के साथ-साथ इन ऋण-व्यवस्थाओं के प्राप्तकर्ता देशों में बुनियादी ढांचागत विकास और क्षमता निर्माण में योगदान देने की प्रतिबद्धता को वैश्विक पटल पर लाने में भी मदद करती हैं। ऋण-व्यवस्थाएं प्राप्तकर्ता देशों के ऐसे बाजारों में जरूरी माल और सेवाओं के निर्यात में भी मददगार हैं, जहां भारत की मौजूदगी न के बराबर है। भारतीय निर्यातक इंडिया एक्ज़िम बैंक से अपने माल के लिए पात्र मूल्य हासिल कर सकते हैं और इसके लिए उन पर किसी तरह का रिकोर्स नहीं रहता। बैंक द्वारा शिपिंग दस्तावेजों के निगोशिएशन/ सेवाओं के प्रावधान के एवज में किया जाता है। भारतीय निर्यातक माल के शिपमेंट पर इंडिया एक्ज़िम बैंक के जरिए पूरा भुगतान ले सकते हैं और इसमें उन्हें क्रेता या क्रेता देश से जुड़े किसी तरह के जोखिम का सामना नहीं करना पड़ता।

ऋण-व्यवस्थाएं संप्रभु सरकारों को या उनकी नामित एजेंसियों को प्रदान की जाती हैं, ताकि उन देशों में क्रेता भारत से माल और सेवाओं का आस्थगित भुगतान शर्तों पर आयात कर सकें। बैंक द्वारा यथा 20 दिसंबर, 2021 को अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, ओशिआनिया और सीआईएस क्षेत्रों के 62 देशों को 27.35 बिलियन यूएस डॉलर की ऋण प्रतिबद्धता के साथ 276 ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान की जा चुकी हैं, जो भारत से निर्यातों के वित्तपोषण के लिए उपलब्ध हैं। इस प्रकार ऋण-व्यवस्थाएं विकासशील देशों में भारत से परियोजनाओं, माल और सेवाओं के निर्यात के संवर्धन और सुगमीकरण के लिए प्रभावी साधन हैं।

इंडिया एक्ज़िम बैंक ने अक्टूबर-दिसंबर 2021 के दौरान भारत सरकार की ओर से निम्नलिखित ऋण-व्यवस्था करार पर हस्ताक्षर किए:

भारत सरकार की ओर से गयाना सरकार को 7.29 मिलियन यूएस डॉलर की ऋण-व्यवस्था प्रदान की गई। यह ऋण-व्यवस्था दूर-दराज के इलाकों में बसे समुदायों के 30,000 घरों के लिए सौर गृह विद्युत प्रणाली की खरीद और इसकी स्थापना के लिए प्रदान की गई है। इस ऋण-व्यवस्था करार पर हस्ताक्षर के साथ ही एक्ज़िम बैंक द्वारा भारत सरकार की ओर से गयाना सरकार को अब तक 117.17 मिलियन यूएस डॉलर की कुल नौ ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान की जा चुकी हैं। गयाना सरकार को प्रदत्त, ये ऋण-व्यवस्थाएं गयाना में ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम संबंधी परियोजना, विश्व कप 2007 के लिए एक क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण, स्थायी एवं कहीं भी लाने ले जा सकने वाले सिंचायी पंपों संबंधी परियोजना, अस्पतालों, ईस्ट बैंक-ईस्ट कोस्ट रोड लिंकेज परियोजना, यात्री-कार्गो जहाज की खरीद, उच्च क्षमता वाले ड्रेनेज पंपों की आपूर्ति और तीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के उन्नयन तथा गयाना के दूर-दराज के इलाकों में बसे समुदायों के 30,000 घरों के लिए सौर गृह विद्युत प्रणाली की स्थापना संबंधी परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए प्रदान की गई हैं।

विस्तृत जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें:

श्री सरोज खुंटिया
महाप्रबंधक
भारतीय निर्यात-आयात बैंक
ऑफिस ब्लॉक, टावर 1, 7वीं मंज़िल, एड्जेसेंट रिंग रोड,
किदवई नगर (पूर्व) नई दिल्ली - 110 023,
फोन :(011) 24607700
ई-मेल: eximloc@eximbankindia.in

दास्तान-ए-कामयाबी

केन्या सरकार को इंडिया एक्ज़िम बैंक की भारत सरकार समर्थित 15 मिलियन यूएस डॉलर की ऋण-व्यवस्था

इंडिया एक्ज़िम बैंक ने केन्या सरकार को केन्या में लघु और मध्यम उद्यमों के विकास के लिए भारत सरकार के सहयोग से 15 मिलियन यूएस डॉलर की ऋण-व्यवस्था प्रदान की है। इस संबंध में ऋण-व्यवस्था करार पर 11 जुलाई, 2016 को हस्ताक्षर किए गए थे।

परियोजना 1: बॉइलर की आपूर्ति, स्थापना और कमीशनिंग

मेसर्स बालककृष्ण बॉइलर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए और 02 जून, 2020 को इस कॉन्ट्रैक्ट को ऋण-व्यवस्था के अंतर्गत शामिल किया गया।

परियोजना के कार्यक्षेत्र में बॉइलर (वर्टिकल एफबीसी थ्री पास थर्मिक फ्लुइड हीटर - वीटीएफ सीरीज़:, बैग फिल्टर (64 बैग) के साथ-साथ इससे संबंधित सभी एसेसरीज़ और सहायक ढांचे एवं फ्लू गैस तथा गर्म हवा डक्टिंग सहित आंतरिक डक्टिंग की आपूर्ति, स्थापना और कमीशनिंग शामिल है।

परियोजना की कुल लागत - 49,027.5 यूएस डॉलर • परियोजना 13 अक्टूबर, 2021 को सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई है।

परियोजना 2: टेक्सटाइल्स के लिए फिनिशिंग मशीन की आपूर्ति, ढांचा खड़ा करना और कमीशनिंग

मेसर्स यमुना मशीन वर्क्स लिमिटेड द्वारा कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए और 18 मई, 2020 को इसे ऋण-व्यवस्था के अंतर्गत शामिल किया गया।

परियोजना के कार्यक्षेत्र में टेक्सटाइल्स के लिए फिनिशिंग मशीन की आपूर्ति, ढांचा खड़ा करना और कमीशनिंग (200 एमएम की कार्यशील चौड़ाई वाली कोटिंग लाइन / स्टेन्टर) शामिल है। इसमें हाई एंट्री के साथ फैब्रिक फीडिंग, दो बॉल पैडर, ऑटोमैटिक बॉ और वेफ्ट स्ट्रेटनर, कोटिंग हेड, छह चैंबर स्टेन्टर, पिन और क्लिप टाइप, क्रश कैलेंडर हॉरिजेंटल टाइप, दो कूलिंग सिलिंडर, प्लेटिंग और बड़ी बैचिंग व्यवस्थाओं के साथ-साथ इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल, ड्रायर, वैरिओ फ्लो एयर सिस्टम, रेडिएटर, डुअल फिल्टर, कूलिंग और डिलीवरी सिस्टम, केबल और केबल ट्रे, ऑयल लाइन वाल्व, टच स्क्रीन वाली पीएलसी और मशीन के लिए आवश्यक पुर्जों की आपूर्ति शामिल है।

परियोजना की कुल लागत - 352,100.0 यूएस डॉलर • परियोजना 20 अगस्त, 2021 को सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई है। ■

वह तिमाही जो थी

एफ्रीनेक्स के साथ लिस्ट हुआ इंडिया एक्ज़िम बैंक का 1 बिलियन यूएस डॉलर का 10 वर्षीय बॉन्ड

भारतीय निर्यात-आयात बैंक (इंडिया एक्ज़िम बैंक) ने एफ्रीनेक्स के साथ अपने 1 बिलियन यूएस डॉलर के 10 वर्षीय बॉन्ड की वर्चुअल लिस्टिंग, 25 अक्टूबर, 2021 को एफ्रीनेक्स के शुभारंभ के दौरान की। श्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ, माननीय प्रधानमंत्री, मॉरीशस सरकार; सुश्री के. नंदिनी सिंगला, मॉरीशस में भारत की माननीय उच्चायुक्त और सुश्री हर्षा बंगारी, प्रबंध निदेशक, भारतीय निर्यात-आयात बैंक ने एफ्रीनेक्स के शुभारंभ के दौरान वर्चुअल माध्यम से इंडिया एक्ज़िम बैंक के 1 बिलियन यूएस डॉलर के 10 वर्षीय बॉन्ड की लिस्टिंग की।

इंडिया एक्ज़िम बैंक का लक्ष्यः 7 बिलियन यूएस डॉलर के परियोजना निर्यातों के लक्ष्य को प्राप्त करना

हाल ही में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाते (एनईआईए) में परियोजना निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए G$1,650 करोड़ राशि की घोषणा के साथ इंडिया एक्ज़िम बैंक का अगले पांच वर्षों में 7 बिलियन यूएस डॉलर के परियोजना निर्यातों का वित्तपोषण करने का लक्ष्य है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मार्च 2006 में स्थापित एनईआईए ट्रस्ट भारत से मध्यम और दीर्घकालिक परियोजना निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए निर्यात ऋण बीमा कवर प्रदान करता है। इस निधि से अगले पांच वर्षों में एनईआईए द्वारा कवर किए जाने वाले परियोजना निर्यातों की संभाव्यता में लगभग G$33,000 करोड़ (4.5 बिलियन यूएस डॉलर के बराबर) की वृद्धि होगी। इस पूंजी से चिह्नित बाजारों में परियोजना निर्यातों की अपार संभावनाओं का दोहन करने में मदद मिलेगी। बैंक ने वर्तमान में एनईआईए कार्यक्रम के अंतर्गत क्रेता ऋण के तहत 14 देशों में 2.74 बिलियन यूएस डॉलर मूल्य की 31 परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की है।

भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई राशि से लाभों के दोहन के लिए भारतीय परियोजना निर्यातकों के साथ अवसरों और चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए इंडिया एक्ज़िम बैंक ने हाल ही में मुंबई में परियोजना निर्यातकों के लिए वैश्विक अवसरों को बढ़ाना विषय पर एक चर्चापरक सत्र का आयोजन किया।

भारत और आसियान के बीच क्षेत्रीय मूल्य श्रृंखला विकास के अवसरः इंडिया एक्ज़िम बैंक

आसियान-भारत केंद्र (AIC) और आसियान-भारत व्यवसाय परिषद के साथ मिलकर, इंडिया एक्ज़िम बैंक द्वारा 18वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन 2021 के क्रम में, 18 अक्टूबर, 2021 को भारत-आसियान संबंधों का विस्तारः व्यवसाय के लिए नए क्षेत्र तलाशना विषय पर एक वेबिनार आयोजित किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि सुश्री रीवा गांगुली दास, सचिव (पूर्व), विदेश मंत्रालय, भारत सरकार ने भारत और आसियान देशों के बीच एक विविध और लचीली आपूर्ति श्रृंखला के विकास की आवश्यकता पर ज़ोर दिया। सुश्री दास ने भारत और आसियान देशों के संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए आपसी व्यापार और निवेश को बढ़ाने के अलावा डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य और दवाओं के क्षेत्र में सहयोग, सतत विकास और बढ़ती कनेक्टिविटी की महत्त्वपूर्ण भूमिका का भी उल्लेख किया।

वेबिनार के दौरान, सुश्री रीवा गांगुली दास, सचिव (पूर्व), विदेश मंत्रालय, भारत सरकार ने मूल्य शृंखला विकासः भारत और आसियान देशों के लिए अवसर विषयक इंडिया एक्ज़िम बैंक के शोध अध्ययन का विमोचन किया। इस दौरान इंडिया एक्ज़िम बैंक की प्रबंध निदेशक सुश्री हर्षा बंगारी, आसियान-भारत व्यवसाय परिषद के को-चेयर श्री दातो रमेश कोडामल और प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस उपस्थित रहे।

बेहतर सहयोग के जरिए व्यापार और निवेश के अलावा अन्य क्षेत्रों में और मजबूत किए जा सकते हैं भारत-जापान संबंधः इंडिया एक्ज़िम बैंक

इंडिया एक्ज़िम बैंक द्वारा 08 अक्टूबर, 2021 को 'भारत-जापान आर्थिक साझेदारी: व्यापार और अन्य संभावनाएं' विषय पर एक वेबिनार आयोजित किया गया। इस दौरान श्री दम्मू रवि, सचिव आर्थिक संबंध, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्चुअल रूप से इंडिया एक्ज़िम बैंक के शोध अध्ययन भारत जापान व्यापार संबंधों को बढ़ाने के लिए संभावनाएं का विमोचन किया गया। इस अवसर पर श्री संजय कुमार वर्मा, जापान में भारत के माननीय राजदूत, श्री शिंगो मियामोटो, मंत्री (आर्थिक एवं विकास), भारत में जापान का दूतावास, इंडिया एक्ज़िम बैंक की प्रबंध निदेशक सुश्री हर्षा बंगारी तथा उप प्रबंध निदेशक श्री एन. रमेश उपस्थित रहे।

इस शोध अध्ययन में कहा गया है कि पिछले एक दशक में जापान के साथ भारत का कुल व्यापार 2019 में 5 बिलियन यूएस डॉलर के निर्यात तथा 13 बिलियन यूएस डॉलर के आयात के साथ 10 बिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर लगभग 18 बिलियन यूएस डॉलर हो गया है। हालांकि, जापान के साथ व्यापक आर्थिक साझेदारी करार (सीईपीए) के बावजूद जापान के साथ भारत का निरंतर व्यापार घाटा चल रहा है और इस दशक के दौरान दोगुने से भी अधिक यानी 2019 में लगभग 8 बिलियन यूएस डॉलर हो गया है। इस अध्ययन में, व्यापार पूरकता विश्लेषण के जरिए उन उत्पाद श्रेणियों की अनुशंसा की गई है, जिनके निर्यातों में भारत की स्थिति बेहतर है। इस शोध अध्ययन में यह भी उल्लेख किया गया है कि खनिज ईंधन और तेल, विद्युत मशीनरी और उपकरण, मशीनरी और यांत्रिक उपकरण, ऑप्टिकल, फोटोग्राफिक उपकरण, दवा उत्पाद, अपैरल और कपड़े आदि जैसी समग्रियों में भारत के निर्यात की महत्त्वपूर्ण संभावनाएं हैं।

भारत से कृषि निर्यातों के लिए वरदान साबित होगी सुदृढ़ व्यापार नीतिः इंडिया एक्ज़िम बैंक का शोध अध्ययन

भारत में कृषि नीतियां उत्पादन बढ़ाने पर केंद्रित रही हैं, ताकि हम आत्मनिर्भर हो सकें, आयातों पर निर्भरता कम हो और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इन प्राथमिक उद्देश्यों के साथ भारत में कीमतों में स्थिरता लाने के अल्पावधि लक्ष्यों को हासिल करने के लिए व्यापार नीति को एक साधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है। इंडिया एक्ज़िम बैंक द्वारा हाल ही में किए गए एक शोध अध्ययन के अनुसार, इस संबंध में भारत सरकार का रुख बदला है। सरकार अब एक सुदृढ़ व्यापार नीति बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि भारत विश्व पटल पर एक विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता के रूप में उभर सके।

इंडिया एक्ज़िम बैंक के भारत से कृषि निर्यातों का संवर्धन शीर्षक वाले इस शोध अध्ययन का विमोचन 12 नवंबर, 2021 को आयोजित भारत से कृषि निर्यातः संभावनाएं और अवसर विषयक वेबिनार के दौरान किया गया। इंडिया एक्ज़िम बैंक द्वारा इस वेबिनार का आयोजन भारत की आजादी के 75 वर्षों के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे आज़ादी का अमृत महोत्सव श्रृंखला के अंतर्गत किया गया। इस वेबिनार में वक्ताओं के रूप में इंडिया एक्ज़िम बैंक, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा), शिक्षाविद और कृषि व्यवसायों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। ■

विभिन्न देशों का आर्थिक परिदृश्य

डी. आर. कांगो

डी.आर. कांगो की अर्थव्यवस्था 2021 में 4.8% और 2022 में 5.3% की दर से बढ़ने का अनुमान है। साल 2021 के मध्य में यहां कामोआ–काकुला तांबा खदान शुरू हो चुकी है। इससे देश की अर्थव्यवस्था में संभावनाएं बलवती हुई हैं। इस परियोजना का चरणबद्ध विस्तार जारी है। इससे अधिक निवेश आकर्षित करने की देश की संभावनाओं को भी बल मिला है। हालांकि मुद्रा के अवमूल्यन और खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि से 2020 में महंगाई दर 11.1% तक बढ़ गई थी। लेकिन 2022 में औसत कीमतों में करीब 9.2% तक का सुधार होने की संभावना है। अल्प अवधि में फ्रैंक (कांगो की मुद्रा) का धीमी गति से अवमूल्यन होने के आसार हैं। साल 2021 के अंत में यहां की मुद्रा फ्रैंक 1 यूएस डॉलर के मुकाबले 1,991.2 एफसी के स्तर पर रही। साल 2022 के अंत में इसके 1 यूएस डॉलर के मुकाबले 2,093.2 एफसी रहने का अनुमान है। चालू खाते का घाटा 2021 में जीडीपी के करीब 2.2% तक पहुंच चुका है। इसके और नीचे जाने की संभावना है। 2022 में इसके जीडीपी का 1.6% और 2023 में जीडीपी का 1.4% रहने का अनुमान है। चालू खाते की स्थिति के लिए कारोबार का सरप्लस और सेवा क्षेत्र की असफलता प्रमुख वजह मानी जा रही है। खनिजों के निर्यात से आय में अच्छी वृद्धि (इसमें क्षमता–वृद्धि और बढ़ते मूल्य दोनों परिलक्षित होते हैं) बने रहने का अनुमान है। यह नियोजित खनन विस्तार के लिए पूंजीगत आयात में वृद्धि और अन्य अवसंरचना संबंधी निवेशों को पीछे छोड़ सकती है। इसके परिणामस्वरूप 2022–23 में व्यापार सरप्लस और बढ़ने का अनुमान है।

चीन

वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 2021 में 7.9% की वृद्धि का अनुमान है। यह 2020 की 2.3% वृद्धि से काफी अधिक है। निवेश बढ़ने की संभावना है। इसके तीन कारण हैं। एक– निजी निवेश में बहाली हुई है। दूसरा– बड़े शहरों में संपत्ति की मांग बढ़ी है। तीसरा– विनिर्मित सामान की घरेलू और बाहरी मांग मजबूत हुई है। जन सेवाओं और स्वास्थ्य पर अधिक खर्च के कारण सरकारी उपभोग के मजबूत रहने का अनुमान है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 2021 में 0.9% तक सुधार होने का अनुमान है। इससे सुअर के मांस की आपूर्ति की बहाली होने का पता भी चलता है। लिहाजा, अब खाद्य कीमतों में गिरावट भी संभावित है। हालांकि खाद्य कीमतों से आगे देखा जाए तो महंगाई का दबाव बने रहने का अनुमान भी है। कारण कि उपभोक्ता मांग मजबूत बनी हुई है और वैश्विक तेल कीमतों के अनुरूप ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है। साथ ही, खराब मौसम ने खाद्य आपूर्ति को भी अस्थाई रूप से प्रभावित किया है। दुनिया के तमाम बाजारों ने कोविड–19 पर काफी हद तक नियंत्रण पा लिया है। इससे निर्यात उत्पादन फिर तेज होने का अनुमान है, जो रेन्मिन्बी (आरएमबी) के अवमूल्यन को खत्म कर सकता है। चीन की मुद्रा का औसत 2021 में आरएमबी 6.45:1 यूएस डॉलर और 2022 में आरएमबी 6.57:1 यूएस डॉलर रह सकता है। वैश्विक जीडीपी वृद्धि की वापसी के सहारे बाहरी व्यापार 2021 में मजबूत रहने की संभावना है। हालांकि चालू खाते के सरप्लस के कारण 2021 में जीडीपी 2.4% और 2022 में 2.3% के करीब रहने का अनुमान है।

सेशेल्स

वैश्विक अर्थव्यवस्था की बहाली और सुधरते कारोबार (मुख्य तौर पर कैन्ड ट्यूना के लिए निर्यात) के चलते सेशेल्स की वास्तविक जीडीपी 2021 में 4.2% की दर से बढ़ने का अनुमान है। हालांकि इसमें आधार–प्रभाव भी परिलक्षित होगा। क्योंकि 2020 में पर्यटन के लगभग पूरी तरह बंद होने से जीडीपी करीब 10.7% तक सिकुड़ गई थी। आर्थिक विस्तार को निर्माण क्षेत्र की गतिविधियों से मदद मिल सकती है। क्योंकि 2021 के अंत तक बड़ी आधारभूत संरचनाओं और जलवायु परिवर्तन संबंधी परियोजनाओं (खासकर मछली पालन और कृषि क्षेत्र में) पर काम शुरू हो सकता है। महंगाई दर यहां 2020 में औसतन 1.2% के करीब रही थी। लेकिन 2021 में इसके 7.8% तक पहुंचने का अनुमान है। पहली तिमाही में मुद्रा के अवमूल्यन और वैश्विक तेल और खाद्य कीमतों में वृद्धि की इसमें प्रमुख भूमिका रहने वाली है। गौर करने लायक है कि सेशेल्स के कुल आयात में खाद्य सामग्री की हिस्सेदारी 25% है। निर्यात आय में बहाली के साथ ही सेशेल्स के रुपये (एसआरएस) के मूल्य में 2021 में सुधार हो सकता है। एसआरएस का मूल्य 17:1 यूएस डॉलर तक रह सकता है। जबकि 2020 में यह एसआरएस 17.6:1 यूएस डॉलर पर था। पर्यटन क्षेत्र के धीरे–धीरे खुलने और देश के प्रमुख पर्यटन बाजार यूरोप में विकास के बल पर सेवा–अधिशेष (सर्विस सरप्लस) में बहाली से चालू खाते का घाटा 2021 में जीडीपी का 24.9% रह सकता है, जो 2020 में जीडीपी का 27.7% था।

ताजिकिस्तान

ताजिकिस्तान की वास्तविक जीडीपी 2021 में अनुमानित 5% की दर से बढ़ने का अनुमान है। इसमें 2020 में 4.5% की वृद्धि हुई थी। तीन चीजें इस विकास को गति दे रही हैं। पहली– मजबूत निर्यात वृद्धि। दूसरी– तुलनात्मक रूप से मजबूत निजी उपभोग की स्थिति। तीसरी– सुनिश्चित निवेश में वृद्धि। गौर करने लायक है कि यहां सरकार ने अर्थव्यवस्था को बचाने के मकसद से कोरोना से जुड़े सख्त प्रतिबंध लागू करने से परहेज किया है। यहां उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 2020 के 8.6% से बढ़कर 2021 में 9.2% तक ऊपर जा सकता है। आपूर्ति में कमी से खाद्य मूल्यों में बढ़ोत्तरी के कारण यह स्थिति बन रही है। केंद्रीय बैंक नियमित परिवर्तनीय विनिमय–दर व्यवस्था को संचालित कर रहा है। यह विनिमय–दर समायोजन की ऐसी व्यवस्था के समान है, जिसमें नियत विनिमय दर वाली मुद्रा को निश्चित दरों में बदलाव की छूट होती है। ताजिकिस्तान की मुद्रा–सोमोनी (एस) का मूल्य 2021 में औसतन एस 11.32:1 यूएस डॉलर रह सकता है। यह 2020 में एस 10.32:1 यूएस डॉलर रहा था। मतलब और अवमूल्यन होने की संभावना है। चालू खाते में सामान्यत: बड़ा व्यापारिक घाटा दर्ज होता है। यह कुछ हद तक प्राथमिक और द्वितीयक आय खातों में विशुद्ध प्रवाह से समायोजित हो जाता है। कम व्यापारिक घाटे के कारण यहां चालू खाते का घाटा 2021 में जीडीपी का 2.5% रहने की संभावना है। यह 2020 में जीडीपी का 4.1% था। ■

मुद्रा की प्रवृत्तियां

जापानी येन

¥ जापानी येन (जेपीवाय) इस साल 10% से अधिक कमजोर हुआ। इससे यह जी-10 देशों में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा बन गई। जनवरी 2017 के बाद पहली बार एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 115 के महत्त्वपूर्ण स्तर को पार कर गई। इसमें दो चीजों की भूमिका रही। पहली- जापान का कमजोर आर्थिक दृष्टिकोण और दूसरा- अमेरिका में उच्च ब्याज दरों की उपेक्षा।

कमजोर येन ने मुद्रास्फीति में और वृद्धि की है। इसने आम परिवारों के साथ-साथ कॉर्पोरेट जगत पर भी असर डाला है। कोविड-19 के कारण पहले से प्रभावित अर्थव्यवस्था में आपूर्ति शृंखला की समस्याएं और जटिल हो गईं तथा उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतें बढ़ गईं। इस सबके बाद अब कमजोर येन के नकारात्मक प्रभाव पहले से ज्यादा होने की आशंका है। क्योंकि इससे आयात पर आनुपातिक रूप से खर्च बढ़ने वाला है। जापान की अर्थव्यवस्था में 2020 तक निर्यात की हिस्सेदारी मोटे तौर पर 15% हो चुकी है। बीते एक अक्टूबर से 10 दिसंबर 2021 के बीच की अवधि में एक यूएस डॉलर की कीमत 110.81 से 115.51 येन के बीच बनी हुई थी।

जबकि 16 दिसंबर, 2021 को यूएस डॉलर 113.70 जापानी येन पर बंद हुआ था।

इथियोपियाई बीर

Br इथियोपियाई बीर (ईटीबी) का मूल्य 1993 के पहले तक यूएस डॉलर के हिसाब से फिक्स यानी सुनिश्चित होता था। बाद में व्यवस्था बदली और 'प्रबंधित परिवर्तनीय विनिमय दर' लागू की गई। इसमें अनिवार्य रूप से अपेक्षित था कि जब भी मुद्रा के मूल्य में असामान्य उतार-चढ़ाव हो तो देश का केंद्रीय बैंक हस्तक्षेप कर उसे प्रबंधित करे।

इस नई व्यवस्था के लागू होने के बाद 'बीर' का निरंतर स्वत: अवमूल्यन हुआ। इसके बावजूद विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने के मकसद से कई मौकों पर सरकार ने भी इसका अवमूल्यन किया गया। सरकार विदेशी विनिमय बाजार को भी दुरुस्त करने की कोशिश में है, जहां विभिन्न कारणों से आधिकारिक विनिमय दर और समानांतर बाजार में अंतर इस वर्ष बढ़ गया है। इसके कारणों में से एक अहम उत्तरी क्षेत्र में जारी संघर्ष भी है। इस सबके अतिरिक्त इथियोपिया उच्च मुद्रा स्फीति की स्थिति का भी सामना कर रहा है। वर्ष-दर-वर्ष आधार पर अक्टूबर 2021 में यहां मुद्रास्फीति 34.8% थी।

अभी 16 दिसंबर, 2021 को यूएस डॉलर 48.5513 ईटीबी पर बंद हुआ था।

श्रीलंकाई रुपया

SLRs श्रीलंका सरकार ने अगस्त के अंतिम सप्ताह में देश में आर्थिक आपातकाल घोषित कर दिया। इसके पीछे प्रमुख कारण थे- बढ़ते खाद्य मूल्य, मुद्रा अवमूल्यन और तेजी से घटता विदेशी मुद्रा कोष। देश के सकल घरेलू उत्पाद में 10% की हिस्सेदारी रखने और विदेशी मुद्रा लाने वाला पर्यटन उद्योग कोरोना वायरस की मार से बहुत अधिक प्रभावित हुआ है। नतीजतन, विदेशी मुद्रा कोष, जो 2019 में 7.5 अरब यूएस डॉलर से अधिक था, वह इस साल सितंबर में कम होकर 2.7 अरब यूएस डॉलर का ही रह गया। श्रीलंकाई रुपये की तेजी से गिरती विनिमय दर ने विदेशी मुद्रा कोष में कमी की रफ्तार को भी तेज किया है। यह भी गौर करने लायक है कि देश को अपनी बुनियादी खाद्य जरूरतों तक के लिए भी आयात पर बहुत अधिक निर्भर रहना पड़ रहा है। इस कारण खाद्य महंगाई पर और ज्यादा असर पड़ा। इतना ही नहीं, सितंबर-2021 में केंद्रीय बैंक ने यूएस डॉलर के मुकाबले 200 रुपये से अधिक मूल्य के वायदा और हाजिर कारोबार पर प्रतिबंध लगा दिया। इस कदम ने बाजार की गतिविधियों को और अधिक प्रभावित किया। इस सबसे श्रीलंकाई रुपये की कीमत इस साल अब तक करीब 9% तक कम हो चुकी है।

श्रीलंका को अगले साल 1.5 बिलियन यूएस डॉलर के कर्ज चुकाने हैं, जिनकी अवधि पूरी हो रही है। इसके लिए देश पर्यटन गतिविधियां फिर शुरू होने से बड़ी उम्मीद लगाए हुए है। देश को कोविड से बुरी तरह प्रभावित पर्यटन क्षेत्र के दोबारा रफ्तार पकड़ने की उम्मीद है। क्योंकि कई बार के लॉकडाउन का सामना करने के बाद अब देश में विभिन्न आर्थिक गतिविधियां दोबारा शुरू हो रही हैं। श्रीलंकाई नागरिकों के अधिक संख्या में रोजगार की तलाश में विदेश जाने से भी उम्मीद है कि अर्थव्यवस्था को बाहर से अधिक धन मिलेगा। सरकार उन प्रवासी कामगारों को प्रोत्साहन राशि की पेशकश भी कर रही है, जो आधिकारिक माध्यमों से धन अपने देश में भेजते हैं। इस कदम का मकसद धन भेजने के अवैध माध्यमों को हतोत्साहित करना और घटते विदेशी मुद्रा कोष को उबारना है।

अभी 16 दिसंबर, 2021 को यूएस डॉलर 201 श्रीलंकाई रुपए पर बंद हुआ था।

चीनी युआन रेन्मिन्बी (सीएनएच)

Rmb सीएनएच वह रेन्मिन्बी (चीन की मुद्रा) है जो चीन के मुख्य भू-भाग से बाहर होने वाले कारोबार में इस्तेमाल होती है। मुख्य रूप से हांगकांग में होने वाले कारोबार में। सीएनएच ने 8 दिसंबर, 2021 को इस वर्ष का शीर्ष और मनोवैज्ञानिक रूप से संवेदनशील स्तर छुआ। यह मुद्रा 6.35 प्रति डॉलर के स्तर को पार कर गई। मई 2018 के बाद से इसका यह सबसे सुदृढ़ स्तर है। विश्लेषक और अर्थशास्त्री इसका श्रेय अत्यधिक निर्यात, रिकॉर्ड व्यापार सरप्लस और प्रचुर डॉलर लिक्विडिटी को देते हैं। केंद्रीय बैंक 'पीबीओसी'ने भी हाल ही में कुछ रियायतें दी हैं। इससे देश में भावनाओं के उभार का जोखिम बना। माना जा रहा है कि यूएस डॉलर की तुलना में सीएनएच के मूल्य में गिरावट का यह एक कारण हो सकता है।

फेडरल रिज़र्व के प्रमुख के रूप में जेरोम पॉवेल के फिर से नामांकित हो जाने के बाद अमेरिका में नीतियों को जल्द से जल्द सख्त किए जाने की अटकलें हैं। इससे अमेरिका में डॉलर को और मजबूती मिली है। हालांकि इस साल चीन की ठोस निर्यात वृद्धि युआन के बेहतर प्रदर्शन में काफी मददगार रही। बावजूद इसके कि चीन के घरेलू प्रॉपर्टी सेक्टर में कुछ गंभीर चिंताएं बनी हुई हैं। दूसरी तरफ, यूएस डॉलर भी लगातार मजबूत हो रहा है।

बीते 16 दिसंबर, 2021 को यूएस डॉलर 6.3797 सीएनएच पर बंद हुआ था। ■

भारतीय अर्थव्यवस्था की कुछ झलकियां

वाणिज्यिक वस्तुओं का कारोबार

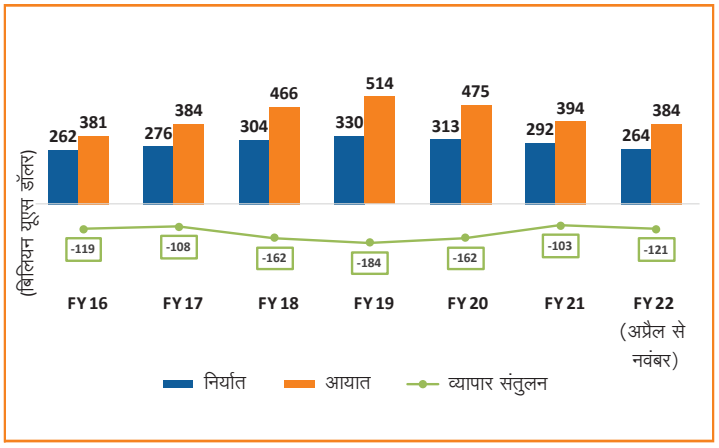

स्रोत: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार

सेवा क्षेत्र में कारोबार

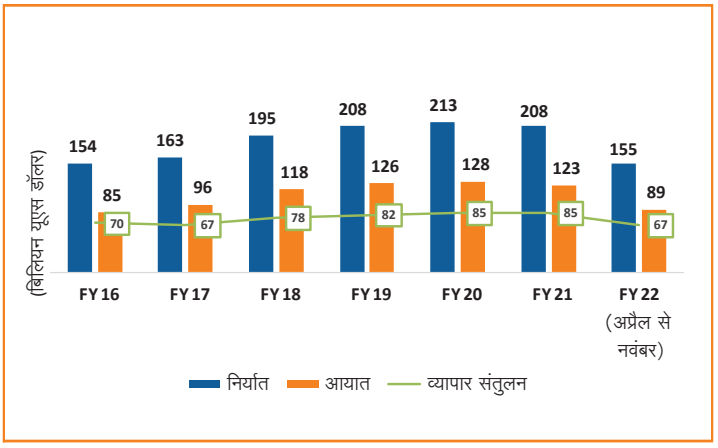

स्रोत: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह

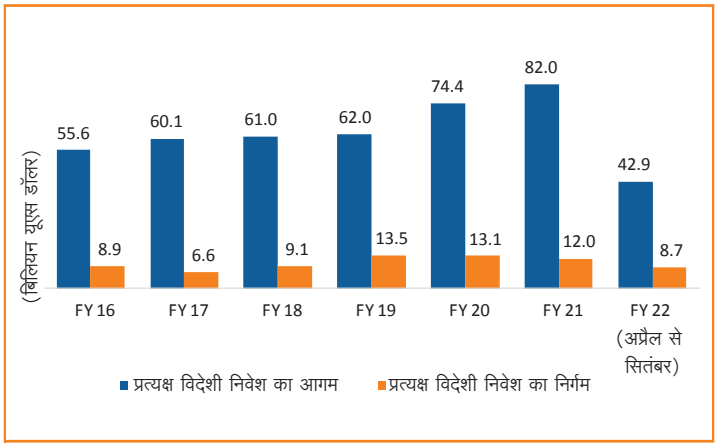

*नोट: *प्रत्यक्ष विदेशी के निवेश के निर्गम में इक्विटी, ऋण और दी गई गारंटियां शामिल हैं*
स्रोत: आरबीआई और वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

उपभोक्ता मूल्य की मुद्रास्फीति

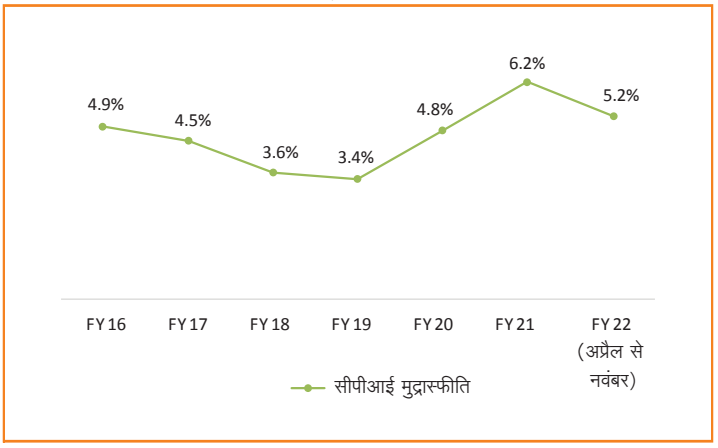

स्रोत : सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार

चालू खाते का घाटा

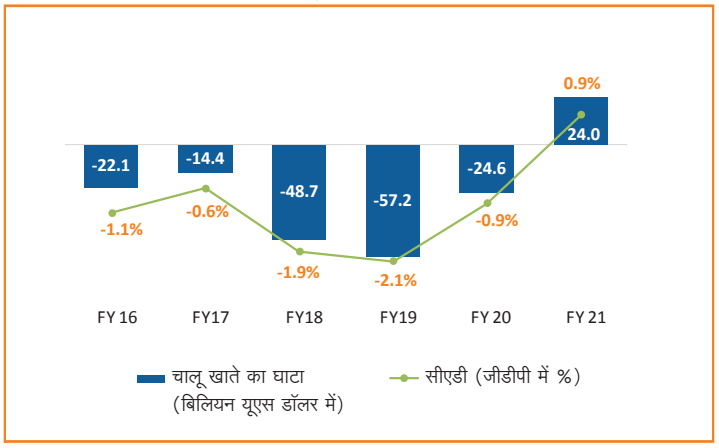

स्रोत : आरबीआई

क्षेत्रवार उत्पादन

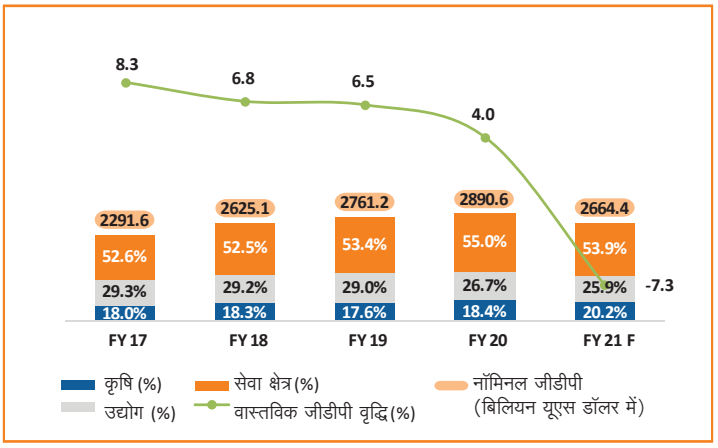

नोट : नॉमिनल जीडीपी (बिलियन यूएस डॉलर में), एफ– पूर्वानुमान
स्रोत : अंतरराष्ट्रीय वित्त संस्थान और सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार